कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत कृषि अखबार

Registered Postal Regn. No.MP/Bhopal/143/2025-27 RNI No. 1832/57 डाक प्रेषण का दिन - सोमवार, मंगलवार

कृषक जगत

राष्ट्रीय कृषि अखबार

भोपाल-जयपुर-रायपुर

ISSN -0970-8650

संस्थापित 1946 भोपाल, प्रकाशन - सोमवार, 9 मार्च 2026 वर्ष - 80 अंक - 28 मूल्य - रु. 12/- कुल पृष्ठ -16 www.krishakjagat.org पृष्ठ- 1

कृषक जगत न्यूज़ वेबसाइट पर जाने के लिए QR कोड स्कैन करें

श्रेष्ठ कृषि पत्रकारिता के लिए भाकृअनुप ICAR चौधरी चरणसिंह अवार्ड से पुरस्कृत

अंदर पढ़िये...

5

श्री अन्न : पोषण सुरक्षा एवं सतत कृषि का आधार

म.प्र. में किसानों को गेहूं पर 40 रु., उड़द पर 600 रु. क्विं. बोनस मिलेगा : डॉ. यादव

भोपाल (कृषक जगत)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार कृषि कल्याण वर्ष 2026 में किसानों की समृद्धि के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। किसानों की फसलों का उचित दाम मिले, इसके लिए उड़द खरीदी पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा की गई है। प्रदेश के किसान उड़द लगाएं, ताकि उन्हें इस बोनस का भरपूर लाभ मिल सके। राज्य सरकार ने गेहूं उत्पादक किसानों को भी बोनस की सौगात दी है। इस वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। इससे किसानों को 2625 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का भुगतान

प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों के साथ समत्व भवन में आयोजित बैठक में यह घोषणा की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कुछ स्थानों पर गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन में कठिनाई सामने आई है। इसे ध्यान में रखकर गेहूं उपार्जन पंजीयन की अंतिम तिथि 7 मार्च से बढ़ाकर 10 मार्च की गई है। रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिये अब तक 12 लाख 4 हजार 708 किसानों ने पंजीयन करा लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, इससे रात के समय बिजली से सिंचाई के कारण होने वाले संकटों से बचा जा सकेगा। बैठक में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, श्री नीरज मंडलोई सहित कृषि, राजस्व, सहकारिता, जल संसाधन, उद्यानिकी तथा अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

श्री अतीश चन्द्रा नए केन्द्रीय कृषि सचिव बने

नई दिल्ली (कृषक जगत)। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री अतीश चंद्रा ने गत 28 फरवरी को भारत सरकार के कृषि सचिव के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। श्री अतीश चंद्रा वर्ष 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और बिहार कैडर से संबंधित हैं। वे मार्च 2021 से भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत थे। उनके पास केंद्रीय भंडारण निगम के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी था।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता : कृषि नीति के लिए नए संकेत

• प्रवेश शर्मा, अध्यक्ष, संचालन समिति, नाफपो पूर्व एमडी, एसएफएसी एवं पूर्व कृषि सचिव, (म.प्र.)

भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौता केवल व्यापार का मुद्दा नहीं है। इसका प्रभाव भारतीय कृषि, किसानों की आय, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था तक पड़ सकता है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि इस समझौते से कृषि क्षेत्र के लिए कौन-से अवसर पैदा हो सकते हैं और कौन-सी नई चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं।

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अंतिम रूप ले रहे व्यापार समझौते के ढांचे को लेकर देश में तीखी बहस जारी है। हालांकि इस समझौते के अंतिम विवरण अभी तय और हस्ताक्षरित होने बाकी हैं, लेकिन इसकी व्यापक रूपरेखा सार्वजनिक क्षेत्र में आ चुकी है और उस पर काफी चर्चा व विश्लेषण हो रहा है। इस लेख में हम इस व्यापार समझौते के उन पहलुओं पर विचार कर रहे हैं, जिनका भारत की कृषि पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है।

इसके संभावित असर का आकलन करते समय यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि हमारे पास अभी तक इस ढांचा समझौते का कोई आधिकारिक या अंतिम दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, जिससे कृषि से जुड़े प्रावधानों की सटीक जानकारी मिल सके। हमारी समझ मुख्यत: मीडिया रिपोर्टों और विशेषज्ञ टिप्पणियों पर आधारित है। स्वाभाविक है कि ये रिपोर्टें राजनीतिक दृष्टिकोणों या संस्थागत प्राथमिकताओं से प्रभावित हो सकती हैं। हम इन संभावित पूर्वाग्रहों से परे रहते हुए सबसे संभावित स्थितियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यह भी ध्यान रखना होगा कि अंतिम समझौता सामने आने के बाद इन आकलनों की पुन: समीक्षा की आवश्यकता पड़ सकती है।

किसी भी नीति निर्णय की तरह, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के परिणाम पूरी तरह सकारात्मक या पूरी तरह नकारात्मक नहीं होंगे। यह मानकर चलना चाहिए कि भारत के वार्ताकारों और नीति-निर्माताओं ने देशहित में सर्वश्रेष्ठ विकल्प सुनिश्चित करने का प्रयास किया होगा।

किसानों के लिए क्या मायने?

इस व्यापार समझौते के बाद किसानों के सामने नई परिस्थितियां बन सकती हैं।

- फसल विविधीकरण की आवश्यकता बढ़ेगी किसानों को पारंपरिक अनाज के साथ बागवानी और पशुपालन जैसे क्षेत्रों की ओर भी देखना होगा।
- गुणवत्ता और मानकों का महत्व बढ़ेगा निर्यात के लिए अंतराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों का पालन करना आवश्यक होगा।
- एफपीओ की भूमिका बढ़ेगी किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से बाजार और निर्यात तक पहुंच आसान हो सकती है।
- तकनीक और जानकारी का महत्व आधुनिक कृषि तकनीक और बाजार जानकारी किसानों के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी।

(शेष पृष्ठ 2 पर)

'कृषि और ग्रामीण परिवर्तन' पर बजट पश्चात वेबिनार में प्रधानमंत्री का संबोधन

कृषि अर्थव्यवस्था का रणनीतिक आधार : श्री मोदी

नई दिल्ली (कृषक जगत)। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गत सप्ताह बजट के बाद आयोजित तीसरे वेबिनार को संबोधित किया। इस वेबिनार का मुख्य विषय 'कृषि और ग्रामीण परिवर्तन' था। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास से संबंधित पिछले सत्रों को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट तैयार करने के दौरान हितधारकों ने बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया। श्री मोदी ने कहा कि अब बजट के बाद, यह उतना ही महत्वपूर्ण है कि देश अपनी पूरी क्षमता का लाभ उठाए और इस दिशा में आपके सुझाव और यह वेबिनार इसलिए महत्वपूर्ण हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार और देश के दीर्घकालिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। श्री मोदी ने 'पीएम किसान सम्मान निधि' और 'न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)' जैसे कई कार्यक्रमों पर बल दिया, जिनसे किसानों को डेढ़ गुना लाभ मिल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र को लगातार मजबूत किया है। अब प्राथमिकता यह है कि बजट प्रावधानों को तेजी से जमीन पर उतारा जाए।

किसानों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूती

श्री मोदी ने 'पीएम किसान सम्मान निधि' और 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' जैसे कई कार्यक्रमों पर बल दिया, जिनसे किसानों को डेढ़ गुना लाभ मिल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र को लगातार मजबूत किया है। सरकार ने किसानों की आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 10 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी जा चुकी है।

कृषि में डिजिटल तकनीक का विस्तार

कृषि क्षेत्र में एग्रीस्टैक और डिजिटल तकनीक के माध्यम से किसान आईडी, भूमि का डिजिटल सर्वे और ई-मार्केट जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे किसानों की बाजार तक पहुंच बढ़ेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस वेबिनार से निकलने वाले सुझाव कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देंगे।

कई राज्यों के राज्यपाल बदले

नई दिल्ली (कृषक जगत)। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ. सी.वी. आनंद बोस का इस्तीफा स्वीकार कर तमिलनाडु के राज्यपाल श्री आर.एन. रवि को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया है। साथ ही राष्ट्रपति ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और उपराज्यपालों की नियुक्ति की है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का राज्यपाल, तेलंगाना के राज्यपाल श्री जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र का, श्री नंद किशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन को बिहार का, केरल के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में कार्यों का निर्वहन करेंगे। लद्दाख के उपराज्यपाल श्री कविंदर गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का उपराज्यपाल तथा श्री तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता ....

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अब राज्य सरकारों, कृषि-व्यवसाय कंपनियों, किसान संगठनों, व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं और अन्य हितधारकों की जिम्मेदारी है कि वे इस बदलते परिदृश्य के अनुरूप स्वयं को तैयार करें। यह लेख कृषि पारितंत्र से जुड़े सभी पक्षों को इस समझौते के संभावित प्रभावों को समझने और उसके अनुसार तैयारी करने में मदद करने का एक प्रयास है। सबसे पहले उन संभावनाओं पर विचार करें, जो अनुकूल परिणाम दे सकती हैं।

फसलों से उच्च मूल्य कृषि की ओर बदलाव

हालांकि अनाज (ज्वार को छोड़कर) को इस समझौते के दायरे से बाहर रखा गया है, फिर भी यह संभावना है कि पशु चारे के लिए डीडीजीएस (डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स विद सॉल्युबल्स) और सोयाबीन तेल के आयात से घरेलू बाजार में मक्का और सोयाबीन की मांग कम हो सकती है। इससे प्रभावित किसान बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन और पोल्ट्री जैसे गैर-फसल क्षेत्रों की ओर रुख कर सकते हैं, जिन्हें प्राय: 'उच्च मूल्य कृषि' कहा जाता है।

मध्यम अवधि में यह परिवर्तन सकारात्मक साबित हो सकता है, क्योंकि उच्च मूल्य कृषि उत्पादों की मांग अनाज और तिलहनों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रही है। हालांकि इस बदलाव के दौरान किसानों को कठिन संक्रमण काल का सामना करना पड़ सकता है। यदि प्रसार सेवाएं, आधुनिक तकनीक, वित्तीय सहायता, अवसंरचना और नए विपणन तंत्र समय पर उपलब्ध नहीं कराए गए, तो यह प्रक्रिया किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

उच्च मूल्य उत्पादों के निर्यात में वृद्धि

उत्पादन बढ़ने के साथ बागवानी उत्पादों विशेषकर फल, सब्जियां और मसालों के निर्यात में वृद्धि की संभावना बन सकती है। लेकिन इसके लिए किसानों को पूर्व और पश्च-फसल प्रबंधन में गुणवत्ता मानकों का प्रशिक्षण देना आवश्यक होगा। साथ ही पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज और अन्य भंडारण सुविधाएं खेतों के निकट उपलब्ध करानी होंगी।

आंतरिक सुधारों की दिशा में दबाव

दीर्घकाल में यह व्यापार समझौता कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों की मांग को तेज कर सकता है। आयात से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए कृषि विपणन प्रणाली विशेषकर अनाज, तिलहन और दलहन जैसी प्रमुख फसलों में सुधार, अनुबंध खेती की स्पष्ट व्यवस्था तथा भंडारण और आवागमन से जुड़े प्रतिबंधों की समीक्षा जैसे कदम आवश्यक हो सकते हैं।

जैव प्रौद्योगिकी और जीएम फसलों पर नई सोच

एक और संभावित सकारात्मक परिणाम यह हो सकता है कि आनुवंशिक रूप से परिवर्तित (जीएम) बीजों और जैव प्रौद्योगिकी के लिए विज्ञान-आधारित, पारदर्शी और भविष्य उन्मुख नियामक व्यवस्था विकसित करने की दिशा में अनुकूल वातावरण बने। कुछ विशेषज्ञों का मत है कि यदि जीएम आधारित फसलों से बने डीडीजीएस और सोयाबीन तेल का आयात हो रहा है, तो भारतीय किसानों को भी उपयुक्त सुरक्षा उपायों के साथ इन तकनीकों तक पहुंच दी जानी चाहिए। इसके लिए नियामक और तकनीकी क्षमता को मजबूत करना आवश्यक होगा। जैसे-जैसे आयात का

भारत-अमेरिका कृषि व्यापार (संकेतात्मक)	
क्षेत्र	**स्थिति**
भारत से अमेरिका निर्यात	मसाले, चाय, कॉफी, चावल, समुद्री उत्पाद
अमेरिका से भारत आयात	बादाम, सेब, दालें, खाद्य तेल
संभावित नए आयात	डीडीजीएस, सोयाबीन उत्पाद
संभावित निर्यात अवसर	फल, सब्जियां, मसाले, प्रसंस्कृत खाद्य

समझौते में चुनौती एवं संभावनाएं

प्रभाव घरेलू बाजार में स्पष्ट होगा, यह बहस और तेज हो सकती है।

संभावित चुनौतियां और जोखिम

अब उन संभावित नकारात्मक पहलुओं पर विचार करें, जो सामने आ सकते हैं।

रकबे में कमी और खाद्य सुरक्षा की चिंता

अल्पावधि में मक्का और सोयाबीन जैसी फसलों के रकबे में कमी देखने को मिल सकती है। डीडीजीएस और सोयाबीन तेल के आयात से पैदा हुई अनिश्चितता इसका कारण बन सकती है। संभव है कि एक-दो वर्षों में स्थिति संतुलित हो जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चिंता यह होगी कि गेहूं और धान जैसी मुख्य खाद्य फसलों के रकबे में कमी न आए, क्योंकि यही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की आधारशिला हैं। आयात के स्वरूप पर लगातार निगरानी रखना आवश्यक होगा।

डेयरी, पोल्ट्री और दलहन पर संभावित प्रभाव

यदि भविष्य में डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद भी समझौते में शामिल किए जाते हैं, तो उच्च मूल्य कृषि की ओर हो रहा विविधीकरण प्रभावित हो सकता है। इसी तरह यदि दलहन के नियमित आयात की अनुमति दी जाती है, तो आत्मनिर्भरता का लक्ष्य कमजोर पड़ सकता है। भारत पहले से ही दलहन का आयात करता है, लेकिन यह एक सोच-समझकर लिया गया निर्णय होता है और समयबद्ध तरीके से किया जाता है। व्यापार समझौते के तहत नियमित आयात इस नीति को प्रभावित कर सकता है।

सामाजिक प्रभाव और ग्रामीण पलायन

बड़े पैमाने पर कृषि आयात ग्रामीण युवाओं को कृषि से दूर कर सकते हैं। पहले से ही कई क्षेत्रों में कृषि कम आय देती है। यदि प्रतिस्पर्धा और बढ़ी, तो युवा बेहतर अवसरों की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर सकते हैं। इससे कौशल उन्नयन और स्थानांतरण की लागत बढ़ेगी, जिससे ग्रामीण ऋणग्रस्तता भी बढ़ सकती है।

राजकोषीय दबाव

बढ़ते आयात से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को सब्सिडी या प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता बढ़ानी पड़ सकती है। इससे राजकोष पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा और विकासात्मक पूंजी निवेश के लिए उपलब्ध संसाधन सीमित हो सकते हैं।

जब तक अंतिम समझौते का पाठ सामने नहीं आता, तब तक ठोस निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। फिर भी उपलब्ध संकेतों से यह स्पष्ट है कि भारतीय कृषि एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। यह समझौता उच्च मूल्य निर्यात, तकनीकी आधुनिकीकरण और नीतिगत सुधार के नए अवसर प्रदान कर सकता है, लेकिन साथ ही खाद्य फसलों और ग्रामीण आजीविकाओं के लिए चुनौतियां भी पैदा कर सकता है।

अंतत: परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकारें, बाजार और किसान कितनी तेजी और समझदारी से परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालते हैं। यदि तैयारी मजबूत रही, संस्थागत क्षमता चुस्त रही और नीतियां साक्ष्य-आधारित रहीं, तो यह समझौता परिवर्तन का माध्यम बन सकता है। अन्यथा, यह कृषि क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक दबाव का कारण भी बन सकता है।

नाफपो के बारे में

नाफपो एक गैर-लाभकारी, बहु-हितधारक राष्ट्रीय मंच है, जो किसान समृद्धि के लिए सशक्त किसान उत्पादक संगठनों के निर्माण के उद्देश्य से कार्य करता है। यह डिजिटल उपकरणों, क्षमता निर्माण, नीतिगत संवाद और बाजार संपर्क के माध्यम से एफपीओ पारितंत्र को मजबूत बनाता है। नाफपो की परिकल्पना ऐसे सशक्त किसान-नेतृत्व वाले संस्थानों की है, जो लघुधारक किसानों को वित्त, तकनीक, बाजार और सुशासन तक पहुंच दिलाकर समावेशी और सतत कृषि परिवर्तन को गति दें।

किसान कल्याण वर्ष 2026 की पहली कृषि कैबिनेट हुई

27 हजार करोड़ से होगा प्रदेश में कृषि और सिंचाई योजनाओं का विकास

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनजाति लोक उत्सव भगोरिया पर बड़वानी के नागलवाड़ी में आयोजित कृषि कैबिनेट के अवसर पर प्रदर्शनी में निमाड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध फसल मिर्च की विभिन्न किस्मों का अवलोकन किया।

भोपाल (कृषक जगत)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बड़वानी जिले के भीलट बाबा देवस्थल, नागलवाड़ी में पहली कृषि कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। बैठक में कृषि, सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य, उद्यानिकी और सहकारिता से जुड़ी 27,500 करोड़ रुपये की योजनाओं को स्वीकृति दी गई। किसान कल्याण वर्ष के तहत हुई इस बैठक में किसानों और उत्पादक गतिविधियों से जुड़े लोगों के लिए 25,678 करोड़ रुपये की योजनाओं पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही नर्मदा नियंत्रण मंडल की बैठक में बड़वानी जिले की दो सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2,068 करोड़ रु. मंजूर किए गए। इन योजनाओं पर राशि अगले पाँच वर्षों में खर्च की जाएगी। किसान कल्याण वर्ष में आगे भी प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कृषि कैबिनेट की बैठकें आयोजित की जाएंगी।

मत्स्य उद्योग नीति-2026 को मंजूरी

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति-2026 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत अगले तीन साल में लगभग 3 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा और करीब 20 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।

मछुआ समृद्धि योजना- 200 करोड़

मंत्रि-परिषद द्वारा मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना को वर्ष 2026-28 में भी जारी रखने के लिए 200 करोड़ रूपये की मंजूरी दी गई।

वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 (5 वर्ष) के लिए स्वीकृत हुई ये योजनाएं

एनएचएम के लिए 1150 करोड़ रूपये

मंत्रि-परिषद ने राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने के लिए 1150 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इस योजना के तहत कृषि क्षेत्र की दक्षता बढ़ाने, विभिन्न कृषि योजनाओं के बेहतर प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए काम किया जाएगा।

कृषि विकास के लिए 3502 करोड़

मंत्रि-परिषद ने 500 करोड़ रुपये से कम लागत वाली कृषि विकास की 20 परियोजनाओं के लिए कुल 3,502 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

पशुधन विकास के लिए 656 करोड़ रुपये : मंत्रि-परिषद ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत सॉर्टेड सेक्स्ड सीमेन उत्पादन परियोजना के लिए 656 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।

पशु स्वास्थ्य के लिए 1723 करोड़ : पशु स्वास्थ्य, पशु संवर्धन और संरक्षण से जुड़ी 14 योजनाओं के लिए भी 1,723 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

सहकारी बैंकों को अंश पूंजी सहायता

मंत्रि-परिषद ने 'सहकारी बैंकों के अंश पूंजी सहायता' योजना को अगले 5 वर्षों तक चलाने के लिए 1,975 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।

किसानों के लिए ब्याज अनुदान योजना

मंत्रि-परिषद ने किसानों को अल्पकालीन फसल ऋण पर ब्याज अनुदान योजना के लिए 3,909 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।

मूंग बीज से बीटी कॉटन तक 'संदेशों' का सिलसिला

दरबारियों का मायाजाल.... और सेम्पल का खेल... कहीं '....भैया' तो नहीं?

इंदौर (कृषक जगत)। प्रदेश में इन दिनों कृषि आदान कारोबार से जुड़े हलकों में तरह-तरह के 'संदेशों' की चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि मूंग के बीज से लेकर बीटी कॉटन के कारोबार से जुड़े लोगों तक इशारों-इशारों में अलग-अलग तरह के पैगाम पहुंचाए जा रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार जिले के कुछ स्थानों पर निरीक्षण, सैंपलिंग और अन्य विभागीय प्रक्रियाओं के नाम पर कंपनियों को संकेत दिए जाने की बातें सामने आ रही हैं। व्यापारिक हलकों में यह भी चर्चा है कि इन संकेतों के साथ 'सैंपल की दहशत से मुक्ति' जैसा माहौल बनाने की बात जोड़ी जा रही है।

बताया जाता है कि इन पैगामों को कंपनियों तक पहुंचाने का काम कुछ तथाकथित 'दरबारी' किस्म के लोग कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब इन संदेशों की कड़ियां जोड़कर देखी जाती हैं तो बातचीत में अंतत: एक ही नाम बार-बार सामने आता है- '... भैया'।

जब प्रदेश में 'कृषक कल्याण वर्ष 2026' मनाने की बात हो रही है, मुख्यमंत्री किसानों के लिए बोनस और नई योजनाएं ला रहे हैं, वहीं 'मामाजी' नए बीज अधिनियम के माध्यम से किसानों को उच्च कोटि का बीज उपलब्ध कराने का भरोसा जता रहे हैं। ऐसे समय में इस तरह के संकेतों और फुसफुसाहटों की चर्चा कृषि आदान कारोबार में कई तरह के सवाल खड़े कर रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि जब किसानों तक गुणवत्तापूर्ण बीज और कृषि आदान पहुंचाने की बात हो रही हो, तब इस तरह की स्थितियां पारदर्शिता और व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं। ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्ष समीक्षा और स्पष्टता आवश्यक मानी जा रही है।

'जैसा बोओगे वैसा काटोगे'

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक **विजय कुमार बोन्द्रिया** द्वारा 14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल से प्रकाशित एवं कृषक जगत 14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, भोपाल (मध्य प्रदेश) से मुद्रित, **सम्पादक : सुनील गंगराड़े,** फोन : 0755-4248100, 2554864, फैक्स : 0755-2571449. E-mail-info@krishakjagat.org इस अंक का मूल्य रु. 12/- वार्षिक शुल्क रु. 600/-.भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय का पंजीयन क्रमांक 1832/57

कृषक जगत
संस्थापक : स्व. माणिकचन्द्र बोन्दिया - स्व. सुरेशचन्द्र गंगराड़े

अमृत जगत

अग्नि स्वर्ण को परखती है, मुसीबत वीर पुरुषों को।

– सेनेका

खाड़ी देशों का संकट और उर्वरकों की उपलब्धता की चुनौती !

पिछले महीने 28 फरवरी 2026 से अमेरिका और इजराईल के बीच शुरू हुए युद्ध की चपेट में खाड़ी के अनेक देश भी आ गए हैं। इससे भारत में कच्चे तेल की आपूर्ति के साथ कृषि के लिए अति आवश्यक उर्वरकों की आपूर्ति भी अछूती नहीं रह सकती। समुद्री परिवहन मार्गों में संभावित बाधा, ऊर्जा बाजार की अनिश्चितता और कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा प्रभाव उर्वरकों की उपलब्धता और कीमतों पर पड़ने की सम्भावना से नकारा नहीं जा सकता। ऐसी अनिश्चितता के समय भारत सरकार द्वारा आगामी खरीफ मौसम से पहले उर्वरकों का पर्याप्त भंडार तैयार करना एक दूरदर्शी कदम माना जाना चाहिए। इससे न केवल किसानों का भरोसा मजबूत होगा, बल्कि यह भी स्पष्ट है कि कृषि उत्पादन की निरंतरता बनाए रखने के लिए सरकार रणनीतिक तैयारी कर रही है। केंद्रीय उर्वरक मंत्रालय के अनुसार वर्तमान समय में देश के पास लगभग 177 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का भंडार उपलब्ध है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 36.5 प्रतिशत अधिक है। पिछले वर्ष जहां यह भंडार लगभग 129.85 लाख मीट्रिक टन था, वहीं अब यह बढ़कर 177.31 लाख मीट्रिक टन हो गया है। यह वृद्धि केवल संख्यात्मक उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह इस बात को अबल मिल रहा है कि भारत ने पूर्व के अनुभवों का लाभ उठाते हुए पहले से तैयारी कर ली है। इसे संयोग ही माना जाना चाहिए कि जारी वैश्विक संकट से निपटने में सरकार द्वारा की गई तैयारी से किसानों को आगामी खरीफ के मौसम में उर्वरकों का संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। कृषि उत्पादन की दृष्टि से उर्वरक भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आदान हैं। देश की बढ़ती जनसंख्या और खाद्यान्न की मांग को देखते हुए खेती की उत्पादकता बढ़ाना अनिवार्य है। हरित क्रांति के बाद से ही रासायनिक उर्वरकों ने कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय योगदान दिया है। आज भी भारतीय खेती की उत्पादकता का बड़ा हिस्सा उर्वरकों की उपलब्धता और उनके संतुलित उपयोग पर निर्भर है। भारत में उर्वरकों का उत्पादन व्यापक स्तर पर होता है, विशेष रूप से यूरिया के उत्पादन में देश ने उल्लेखनीय आत्मनिर्भरता हासिल की है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कई संयंत्र प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में यूरिया का उत्पादन करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने बंद पड़े संयंत्रों को फिर से चालू करने और नए संयंत्र स्थापित करने की दिशा में उल्लेखनीय काम किया है। इसके परिणामस्वरूप घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई है और आयात पर निर्भरता कुछ हद तक कम हुई है। वर्तमान में देश में उपलब्ध उर्वरकों में यूरिया का

भंडार लगभग 59.30 लाख मीट्रिक टन बताया गया है, जो किसानों की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हालांकि भारत में यूरिया का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन कुछ प्रमुख उर्वरकों के मामले में देश अभी भी आयात पर निर्भर है। इनमें प्रमुख रूप से डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट), एमओपी (म्यूरेट ऑफ पोटाश) और एनपीके मिश्रित उर्वरक शामिल हैं। फॉस्फेट और पोटाश के कच्चे खनिज भारत में सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, इसलिए इनका आयात करना पड़ता है। यही कारण है कि वैश्विक बाजार में किसी भी प्रकार की राजनीतिक या आर्थिक अस्थिरता का असर इन उर्वरकों की उपलब्धता पर पड़ता है। उर्वरक विभाग के अनुसार वर्तमान भंडार में डीएपी लगभग 25.13 लाख मीट्रिक टन और एनपीके उर्वरकों का भंडार लगभग 55.87 लाख मीट्रिक टन है। यह मात्रा आगामी खरीफ सीजन की मांग को देखते हुए संतोषजनक मानी जा रही है। इसके साथ ही सरकार ने आयात के मोर्चे पर भी सक्रिय रणनीति अपनाई है। फरवरी 2026 तक भारत लगभग 98 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का आयात कर चुका है और अगले तीन महीनों में 17 लाख मीट्रिक टन से अधिक अतिरिक्त आयात की व्यवस्था की गई है। उर्वरकों का बाजार पूरी तरह वैश्विक कारकों से प्रभावित होता है। ऊर्जा की कीमतें, प्राकृतिक गैस की उपलब्धता, समुद्री परिवहन मार्गों की स्थिति और प्रमुख उत्पादक देशों की नीतियां, ये सभी उर्वरक उत्पादन और आपूर्ति को प्रभावित करते हैं। विशेष रूप से यूरिया उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। इसलिए गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करना भी उर्वरक सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार ने इस दिशा में भी सक्रियता दिखाई है। हाल ही में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकों में यह स्पष्ट किया गया कि उर्वरक क्षेत्र को गैस की आपूर्ति राष्ट्रीय प्राथमिकता बनी रहेगी। इसके साथ-साथ उर्वरक कंपनियों ने भी अपनी उत्पादन रणनीति को परिस्थिति के अनुसार ढालना शुरू किया है। वर्तमान समय को उर्वरक उद्योग में 'लीन पीरियड' माना जाता है, जब कई संयंत्रों में रखरखाव और मरम्मत का काम किया जाता है। लेकिन वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए कंपनियों ने अपने निर्धारित रखरखाव कार्य पहले ही पूरा करने का निर्णय लिया है ताकि खरीफ सीजन के दौरान उत्पादन में किसी प्रकार की बाधा न आए। फिर भी यह प्रश्न उठता है कि क्या केवल भंडारण और आयात से समस्या का स्थायी समाधान संभव है? दीर्घकालीन रणनीति के तहत में भारत को उर्वरकों के क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में और कदम उठाने की जरूरत है। इसके लिए फॉस्फेट और पोटाश के वैकल्पिक स्रोतों की खोज, विदेशों में खनिज संपदाओं में निवेश और जैव-उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है। इसके साथ ही उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर भी ध्यान देना जरूरी है। भारत में लंबे समय से यूरिया का अत्यधिक उपयोग और फॉस्फेट-पोटाश उर्वरकों का अपेक्षाकृत कम उपयोग देखा गया है। इससे मिट्टी की उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए सरकार की 'नैनो यूरिया', 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' और संतुलित पोषण की योजनाएं भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। कृषि प्रधान भारत में करीब 15 करोड़ किसानों को यदि समय पर बीज, पानी और उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित हों तो वे हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। ऐसे में सरकार और उर्वरक उद्योगों की जिम्मेदारी बनती है कि खेतों तक उर्वरक की आपूर्ति बिना किसी बाधा के जारी रहे। इससे भारत की खाद्य सुरक्षा और मजबूत अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान सतत जारी रह सकता है।

'ट्रेड-डील' में सोयाबीन : पिछले दरवाजे से प्रवेश देने का कारनामा

● अरविंद सरदाना

भारत-अमेरिका के बीच प्रस्तावित 'ट्रेड डील' में यह दावा किया गया है कि खेती और किसान हित पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन जब इसके प्रावधानों की तह में जाते हैं, तो तस्वीर उतनी साफ़ नहीं दिखती। सतह पर सुरक्षा का आश्वासन है, पर बारीकियों में कई ऐसे प्रावधान छिपे हैं जो किसानों, विशेषकर सोयाबीन उत्पादकों के लिए गंभीर चुनौती बन सकते हैं।

केवल सोयाबीन के संदर्भ पर ध्यान केंद्रित करें तो दो ऐसी आयातित वस्तुएँ हैं, जो यदि अमेरिका से भारत में बड़े पैमाने पर प्रवेश करती हैं, तो देश के किसानों को भारी नुकसान पहुँचा सकती हैं। इसमें पहला है, 'डीडीजीएस' (डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स विद सोल्यूबल्स)। यह इथेनॉल उत्पादन प्रक्रिया (मुख्यतः मक्का) से बचा हुआ एक उच्च प्रोटीन और पौष्टिक उप-उत्पाद है, जिसका उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। यह फाइबर, प्रोटीन और वसा से भरपूर होता है, जो मवेशियों, पोल्ट्री और मछली के लिए एक बेहतरीन आहार है।

अमेरिका में मक्का से बड़े पैमाने पर इथेनॉल का उत्पादन होता है जिसके निर्माण के बाद जो अवशेष बचता है, वह एक प्रकार की खली होती है। अब तक भारत में इसे अनुमति नहीं दी गई थी, क्योंकि इससे देश में उत्पादित सोयाबीन खली के बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। यदि सस्ती दरों पर 'डीडीजीएस' का आयात होता है, तो पशु-आहार उद्योग घरेलू सोयाबीन खली की जगह इस आयातित विकल्प को प्राथमिकता देगा। इसका सीधा असर सोयाबीन की मांग और कीमतों पर पड़ेगा, जिससे किसानों की आय प्रभावित होगी। सबसे बडी चिंता यह है कि अमेरिका में उत्पादित

अधिकांश मक्का 'जीएम' यानि अनुवांशिक रूप से संशोधित है। भारत में 'जीएम' खाद्य एवं फीड पर सख्त प्रतिबंध और नियामक नियंत्रण हैं। ऐसे में 'डीडीजीएस' का आयात न केवल आर्थिक, बल्कि जैव-सुरक्षा और नीतिगत प्रश्न भी खड़े करता है।

अमरीका के साथ हुई हाल की 'ट्रेड-डील' के बारे में जितना, जो कुछ पता चल रहा है उससे उजागर हो रहा है कि यह 'डील' भारत के किसानों के लिए भांति-भांति के संकट खड़े करेगी। सोयाबीन उनमें से एक है।'ट्रेड- डील' में सोयाबीन की बदहाली पर बता रहे है अरविंद सरदाना।

दूसरा, कच्चा सोयाबीन तेल। यदि अमेरिका से कच्चा सोयाबीन तेल आयात कर केवल भारत में उसका रिफाइनिंग किया जाता है, तो इसका लाभ प्रसंस्करण उद्योग को तो मिल सकता है, परंतु घरेलू सोयाबीन उत्पादकों को नहीं। इससे भारतीय किसानों द्वारा उत्पादित सोयाबीन की खपत और कीमत दोनों प्रभावित होंगी। सोयाबीन की स्थानीय खली के मुकाबले आयातित 'डीडीजीएस' सस्ता पड़ता है। इस कारण इसका पशु-आहार में उपयोग बढ रहा है। अभी तक इन दोनों में घरेलू बाज़ार में कुछ प्रतिस्पर्धा है। अमेरिका से आयात के बाद यह प्रतिस्पर्धा बहुत तेज हो जाएगी, क्योंकि यह और भी सस्ता होगा। अभी आयात पर कोटा लगाया गया है - केवल 5 लाख टन ही आयात कर सकते हैं, परन्तु एक बार दरवाज़ा खोल दिया, तो यह बढ़ता ही जाएगा।

यह चिंताजनक है, क्योंकि देशी सोयाबीन का बाज़ार मूल रूप से बदल गया है। कारखाने पहले अधिकमात्र में इसका निर्यात करते थे, अब उनका 80 प्रतिशत बाज़ार घरेलू माँग से पूरा होता है। अमेरिकी 'डीडीजीएस' आयात से सोयाबीन खली का भाव गिरेगा। खली का भाव गिरते ही मंडी में सोयाबीन का भाव गिरेगा। इस पर ध्यान देना चाहिए कि सोयाबीन तेल और उसकी खली जुड़वा उत्पाद हैं। वज़न के हिसाब से सोयाबीन में तेल केवल 20 प्रतिशत है, बाकी खली है। कारखाने के लिए मूल्य के हिसाब से देखें तो खली के कारण 60 प्रतिशत आय होती है। वर्तमान परिस्थिति में कारखाने देशी खली को घरेलू बाज़ार में ही बेच पाएँगे। निर्यात के मौके सीमित हैं। अमेरिका की खली का आयात सोयाबीन के भाव को कमज़ोर करेगा। इसे रोकना चाहिए।

अमेरिका से आयात की अनुमति सूची में सोयाबीन तेल को जोड़ा गया है। सोयाबीन के कच्चे तेल के आयात पर अभी 16.5 प्रतिशत आयात शुल्क लगता है। अमेरिका से आयात करने पर क्या शुल्क होगा, अभी सौदेबाज़ी की स्थिति में है। यदि अमेरिका के लिए आयात-शुल्क कम कर दिया तो इसका गंभीर प्रभाव होगा। तेल का भाव गिरेगा और कारखाने अपनी माँग और कम कर देंगे। इसका सीधा असर सोयाबीन के भाव और उसकी खेती पर होगा। यदि मंडी भाव 3000 से 3500 पर आ जाए तो इससे उबरना संभव नहीं होगा। यहां भावान्तर भी नहीं चलेगा।

एक विडंबना है कि सोयाबीन प्रोटीन युक्त है और हमारे देश में प्रोटीन की कमी है, पर हम इसे अपने खान-पान में पर्याप्त शामिल नहीं कर पा रहे हैं। बाज़ार बढ़ाने के लिए सोयाबड़ी का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। साथ ही सोया आटे को अन्य आटे में मिलाया जा सकता है। सवाल यह है कि क्या 'खेती को सुरक्षित रखने' का आश्वासन केवल एक औपचारिक वाक्य है, या वास्तव में किसानों के हितों की रक्षा के लिए ठोस सुरक्षा प्रावधान भी मौजूद हैं? 'ट्रेड डील' केवल व्यापार का दस्तावेज़ नहीं होती - वह लाखों किसानों की आजीविका, बाजार संरचना और खाद्य सुरक्षा की दिशा तय करती है। इसलिए आवश्यक है कि सोयाबीन जैसे संवेदनशील कृषि उत्पादों के संदर्भ में हर प्रावधान को पारदर्शिता और दूरदर्शिता के साथ रखा जाए।

(सप्रेस)

श्री अन्न : पोषण सुरक्षा एवं सतत कृषि का आधार

● डॉ. डी. सी. श्रीवास्तव, वरिष्ठ वैज्ञानिक
कृषि विज्ञान केंद्र, छिंदवाड़ा

वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन, घटती कृषि योग्य भूमि एवं कुपोषण जैसी समस्याएँ कृषि क्षेत्र के समक्ष गंभीर चुनौती के रूप में उपस्थित हैं। इन परिस्थितियों में श्री अन्न (मोटा अनाज) खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुरक्षा दोनों को सुदृढ़ करने का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। वर्ष 2023 को यूनाइटेड नेशन्स द्वारा अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया, जिससे इन फसलों को वैश्विक स्तर पर नई पहचान प्राप्त हुई। श्री अन्न मोटे अनाजों का समूह है, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी (मडुआ), जौ, कोदो, कुटकी, सामा (सांवा), कंगनी तथा चीना आदि शामिल हैं। ये अनाज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं तथा कम उपजाऊ, वर्षा आधारित एवं ढालू भूमि में भी सफलतापूर्वक उगाए जा सकते हैं। कम लागत एवं न्यूनतम संसाधनों में उत्पादन संभव होने के कारण यह आर्थिक रूप से कमजोर एवं जनजातीय किसानों के लिए अत्यंत उपयुक्त फसल है।

मध्यप्रदेश में श्री अन्न की स्थिति

मध्यप्रदेश में लगभग 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में श्री अन्न की खेती की जाती है। मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, जबलपुर एवं शहडोल जिलों में कोदो, कुटकी एवं रागी का प्रमुख उत्पादन होता है। छिंदवाड़ा जिले में भी श्री अन्न के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इन फसलों की उन्नत किस्मों का विकास किया गया है। कोदो की JK-137, JK-76, JK-98; कुटकी की JK-36, JK-4, JK-95 तथा रागी की JNR-852, JNR-781-2 एवं JNR-1008 प्रमुख किस्में हैं।

राज्य शासन की योजनाएँ

मध्यप्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना-राज्य शासन द्वारा वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के लिए इस योजना को लागू किया गया है। इसके अंतर्गत किसानों को उन्नत प्रमाणित बीज 80 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण, अध्ययन भ्रमण, मेले एवं कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं।

रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना

इस योजना के अंतर्गत श्री अन्न उत्पादक किसानों को प्रति क्विंटल 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि एवं 3,900 रुपये प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त है। योजना का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाना एवं किसानों की आय में वृद्धि करना है।

प्रसंस्करण एवं तकनीकी विकास

मिलेट के दाने छोटे एवं कठोर होते हैं तथा उनका छिलका मजबूत होता है, जिससे पिसाई में कठिनाई होती है। उचित प्रसंस्करण के लिए सफाई, ग्रेडिंग, डिहलिंग एवं नमी नियंत्रण आवश्यक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग द्वारा मिलेट प्रसंस्करण हेतु आधुनिक यंत्र विकसित किए गए हैं, जैसे मिलेट क्लीनर कम ग्रेडर, डिहस्कर, डेस्टोनर, पॉलिशर, फर्मेंटर, फ्लोर मिल एवं रोस्टर। इनसे श्रम की बचत एवं गुणवत्ता में सुधार संभव हुआ है।

श्री अन्न की पोषण संबंधी विशेषताएँ

श्री अन्न में संतुलित अमीनो अम्ल, प्रचुर मात्रा में फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन एवं विटामिन पाए जाते हैं। रागी विशेष रूप से कैल्शियम का उत्कृष्ट स्रोत है। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने के कारण यह मधुमेह रोगियों के लिए लाभकारी है।

भंडारण एवं उपयोग

अन्य अनाजों की तुलना में श्री अन्न का भंडारण अधिक समय तक किया जा सकता है। हालांकि आटे के रूप में इसे अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, अतः नियंत्रित नमी एवं उचित प्रसंस्करण आवश्यक है। फर्मेंटेशन तकनीक से इसकी पौष्टिकता एवं भंडारण अवधि में वृद्धि की जा सकती है।

किसान सहायता एवं परामर्श

किसानों को कृषि संबंधी मार्गदर्शन हेतु किसान सारथी हेल्पलाइन (1800-123-2175 / 14426) तथा किसान कॉल सेंटर (1800-180-1551) की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ स्थानीय भाषा में विशेषज्ञ सलाह प्रदान की जाती है।

श्री अन्न केवल पारंपरिक अनाज नहीं, बल्कि पोषण सुरक्षा, जलवायु अनुकूल कृषि एवं किसान आय वृद्धि का सशक्त माध्यम है। आवश्यक है कि शासन और वैज्ञानिक संस्थानों के साथ ही किसान और आमजन सभी मिलकर इसके उत्पादन, प्रसंस्करण एवं उपभोग को प्रोत्साहित करें, जिससे देश के नागरिकों की पोषण संबंधी जरूरतों को प्रतिदिन के खान पान माध्यम से सुनिश्चित कर स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस प्रगति सुनिश्चित की जा सके।

स्वास्थ्य में महत्व

श्री अन्न का नियमित सेवन हृदय स्वास्थ्य को सुदृढ़ करता है, पाचन तंत्र को सुधारता है, वजन नियंत्रण में सहायक होता है तथा हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण लिवर स्वास्थ्य में भी सहायक होते हैं।

कृषक जगत के स्वामित्व के संबंध में घोषणा
फार्म - 4

रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एण्ड बुक अधिनियम की धारा-8 के अंतर्गत-कृषक जगत के पत्र स्वामित्व व अन्य विषयों का विवरण-

1.	प्रकाशक	- 14,इंदिरा काम्पलेक्स एम.पी. नगर भोपाल-462011
2.	प्रकाशक की अवधि	- साप्ताहिक
3.	प्रकाशक का नाम	- विजय कुमार बोन्द्रिया
4.	राष्ट्रीयता	- भारतीय
5.	सम्पादक	- सुनील गंगराड़े
6.	उन व्यक्तियों के नाम पते जो समाचार पत्र के मालिक अथवा साझेदार 1 प्रतिशत से अधिक से हिस्सेदार हैं	- विजय कुमार बोन्द्रिया सुनील गंगराड़े डॉ. साधना गंगराड़े सचिन बोन्द्रिया अजय बोन्द्रिया - 14,इंदिरा काम्पलेक्स एम.पी. नगर भोपाल-462011

मैं विजय कुमार बोन्द्रिया घोषणा करता हूं कि ऊपर दिया गया विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है.

विजय कुमार बोन्द्रिया
प्रकाशक

ऑनलाईन सदस्यता के लिए लॉग इन करें
www.krishakjagat.org

भिण्डी की खेती से आय

● आशीष शर्मा ● शोभाराम अंजनावे
● सुनील कुमार पाण्डेय ● विकास जैन
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, पवारखेड़ा, नर्मदापुरम्
● चन्द्र शेखर पाण्डेय ● रजनी शर्मा
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, जबलपुर

भिण्डी की खेती उष्ण तथा उष्णकटिबंधिय क्षेत्रों में एक वार्षिक सब्जी के रूप में की जाती है। कोमल हरे फलों से करी और सूप बनाया जाता है। इसकी जड़ तथा तने का उपयोग गुड़ बनाते समय ज्यूस केन स्वच्छ करने में किया जाता है। इसमें फल में अधिक मात्रा में आयोडीन होने से ''गोइटर'' रोग का नियंत्रण किया जाता है। इसके अलावा गुर्दे का दर्द, ल्यूकोरिया तथा सामान्य कमजोरी में भी सहायक होता है भिण्डी के सुखे बीज में 13-20 प्रतिशत खाने योग्य तेल तथा 20-24 प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है। इसके तेल का उपयोग साबुन कॉस्मेटिक उद्योगों में किया जाता है। क्रश किए बीजों से दूध उत्पादन के लिए घरेलू जानवरों को खिलाया जाता है तथा रेशों का उपयोग जूट, कपड़ा तथा कागज उद्योगों में किया जाता है। इसकी खेती उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा में प्रमुख रूप से की जाती है।

मृदा :- इसकी खेती के लिए दोमट भूमि अच्छी रहती है परन्तु इसकी खेती बलुई मिट्टी एवं चिकनी मिट्टी में भी की जा सकती है। उचित जल निकास वाली तथा पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक पदार्थ वाली भूमि इसकी खेती के लिए आदर्श होती है। भूमि का पी.एच. 6-6.8 होना आवश्यक है।

भूमि की तैयारी :- भूमि की अच्छी तैयारी के लिऐ एक गहरी जुताई तथा 3-4 सामान्य जुताई करें। भिण्डी में टेपरूट सिस्टम होने के कारण पौधा अच्छी तरह से विकसित होता है। और पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है। भूमि में पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक पदार्थ हो। इसलिये भूमि की तैयारी के समय अच्छी तरह पकी हुई गोबर या कम्पोस्ट की खाद मिलायें। अन्तिम जुताई के समय फास्फोरस तथा पोटाश की सम्पूर्ण मात्रा तथा नाईट्रोजन की आधी मात्रा मिला दें एवं अन्तिम जुताई के बाद भूमि को समतल कर दें।

बुआई का समय और बीज दर

ग्रीष्म ऋतु : ग्रीष्म ऋतु में इसकी बुआई मध्य फरवरी से अन्तिम मार्च तक की जा सकती है। इस ऋतु में 18-22 किलो ग्राम प्रति हेक्टर बीज की आवश्यकता होती है।

है। इसलिये वर्षा ऋतु में उचित जल निकास तथा ग्रीष्म ऋतु में उचित अंकुरण तथा सिंचाई के लिए मेड विधि से बुआई करें। बीज की बुआई नम भूमि में करने के बाद तुरन्त सिंचाई करें।

ग्रीष्मऋतु में वानस्पतिक वृद्धि कम होती है इसलिये कतार से कतार की दूरी 45 से.मी. तथा पौधे से पौधे की दूरी 20 से.मी. रखी जाती है तथा वर्षाऋतु में पौधो की वानस्पतिक वृद्धि अधिक होती है इसलिये कतार से कतार की दूरी 45-60 से.मी. तथा पौधों से पौधों की दूरी 25-30 से.मी. रखी जाती है।

बीज एवं भूमि उपचार : बीज उपचार के लिए 0.2 प्रतिशत बाविस्टीन का घोल बनाकर बीज को डुबायें जिससे अंकुरण प्रक्रिया जल्दी होती है। तथा शुरूआती दिनों में पौधे को मृदा जनित बीमारी से बचाये जा सकते हैं। 2 कि.ग्रा. कार्बोफ्यूरॉन से भूमि का उपचार करें ताकि

वर्षा ऋतु : वर्षाऋतु में इसकी बुआई जून-जुलाई में की जाती है वर्षा ऋतु में 8-10 किलो ग्राम प्रति हेक्टर बीज की आवश्यकता होती है।

बुआई की विधि एवं अंतराल : भिण्डी की बुआई पौध रोपण के माध्यम से की जा सकती है परन्तु कम ही सफल होती है। बीज को सीडड्रिल से सीधे बुआई की जाती है। छिड़काव विधि से बुआई नहीं करें क्योंकि इस विधि में अधिक बीज दर कर्षण क्रियाओं तथा कटाई में असुविधा होती

रूटनॉट नेमाटोड तथा कीटों को 4-5 सप्ताह तक नियंत्रण किया जा सकता है।

खाद एवं उर्वरक : मृदा परीक्षण के आधार पर ही खाद एवं उर्वरक की मात्रा निर्धारित करें। भिण्डी की फसल के लिए खाद एवं उर्वरक की मात्रा अनुशंसित की गई है। जिसमें 15-20 टन गोबर या कम्पोस्ट की खाद, 125 कि.ग्रा. नाइट्रोजन, 75 कि.ग्रा. फास्फोरस तथा 60 कि.ग्रा. पोटाश प्रति हेक्टर दें। गोबर की खाद या कम्पोस्ट खाद की सम्पूर्ण मात्रा नाइट्रोजन की एक तिहाई तथा फास्फोरस एवं पोटाश की सम्पूर्ण मात्रा खेत की तैयारी के समय दें। तथा शेष नाइट्रोजन को दो भागों में बांटकर बुआई के 30 दिन बाद तथा फूल आने के समय पर छिड़काव विधि से दें।

सिंचाई : बीज की बुआई नम भूमि में करें। बसंत एव ग्रीष्म ऋतु में प्रथम पत्ती निकलने पर प्रथम सिंचाई करें। ग्रीष्म फ़सल में 4-5 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। यदि तामपान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो तो नियमित सिंचाई करने पर उचित फलन प्राप्त होते हैं। टपकाव विधि से सिंचाई करने पर उपज में वृद्धि होती तथा 70-80 प्रतिशत पानी की बचत होती है। भिण्डी की फसल में सिंचाई के लिए, बाढ़ विधि के बजाय कूड़ विधि बेहतर होती है। फूल आने तथा फल जमाव के समय नमी की कमी होने पर लगभग 70 प्रतिशत तक उपज में हानि होती है। फल जमाव तथा विकास के समय पौधा मृदा से अधिक मात्रा में पोषक तत्व लेते हैं। अगर इस समय मृदा में पानी की कमी होती है तो न केवल उपज कम होगी अपितु फल में पोषण संबंधी स्तर भी प्रभावित होती है।

खरपतवार नियंत्रण : बसंत और ग्रीष्म की फसल में दो से तीन बार निंदाई गुड़ाई करें तथा खरीफकी फसल में नियमित रूप से खरपतवार निकालते रहें। भिण्डी में उचित खरपतवार प्रबंधन से 90 प्रतिशत हानि होने से बचाया जा सकता है। खरपतवार अधिक होने पर फ्लूक्लोरालीन (बासालीन 48 ईसी) 1.5 किग्रा प्रति हेक्टर के हिसाब से बुआई से पहले तथा पेण्डीमिथालिन (स्टॉम्प 30 ईसी) 0.75 कि.ग्रा. प्रति हेक्टर के हिसाब से खरपतावर निकलने के बाद छिड़काव करें।

तुड़ाई : जल्दी कटाई करने से कम उपज प्राप्त होती है साथ ही कोमल फलों की भण्डारण अवधि भी कम होती है। सामान्यत: भिण्डी की तुड़ाई एक दिन छोड़कर करें। उपभोक्ता जिसकी लम्बाई 7-10 से.मी. छोटे कोमल फल पसन्द करते हैं। भिण्डी के फलने को सुरक्षित रखने के लिए सस्ते हाथ दस्ताने या कपड़े का थैला उपयोग करें। भिण्डी की तुड़ाई सुबह के समय करें। परन्तु दूर के बाजारों में ले जाने के लिऐ शाम के समय तुड़ाई करना उचित रहता है। तथा रात में ही परिवहन के माध्यम से अन्य शहरों में पहुंचाया जा सकता है।

उपज : ग्रीष्म ऋतु में 60-70 क्विंटल प्रति हेक्टर तथा खरीफमें 100-120 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज प्राप्त होती है।

उन्नत किस्में

वर्षा उपहार :- यह प्रजाति येलो वेन मोजेक विषाणु रोगरोधी है। पौधे मध्यम ऊँचाई वाले (90-120 से.मी.) तथा इनके इन्टरनोड पास-पास होते है। पौधों मे 2-3 शाखायें प्रत्येक नोड से निकलती है। पत्तियों का रंग गहरा हरा, निचली पत्तियां चौड़ी तथा छोटे-छोटे लोब्स वाली एवं ऊपरी पत्तियां बड़े लोब्स वाली होती है। वर्षा ऋतु में 40 दिनों में फूल निकलना शुरू हो जाते है तथा फल 7 दिनों बाद तोड़े जा सकते है। फल चौथी-पॉचवी गांठों से पैदा होते है। औसत पैदावार 9-10 टन प्रति हेक्टर होती है। इसकी खेती ग्रीष्म ऋतु में भी कर सकते है।

अर्का अनामिका :- यह प्रजाति येलो वेन मोजेक विषाणु रोग रोधी है। इसके पौधे ऊंचे (100 से.मी.) सीधे तथा अच्छी शाखायुक्त होते हैं फल 20 से.मी. लम्बे तथा मध्यम आकार के होते है फल रोमरहित, मुलायम, गहरे हरे तथा 5 धारियों वाले होते हैं। फलों के डण्ठल लम्बे होने के कारण तोड़ने में सुविधा होती है। यह प्रजाति दोनों ऋतुओं में उगायी जा सकती है। पैदावार 125 क्विंटल प्रति हेक्टर हो जाती है।

अर्का अभय : यह प्रजाति येलोवेन मोजेक विषाणु रोग रोधी है। इसके पौधे ऊंचे 120-150 से.मी. सीधे तथा अच्छी शाखा युक्त होते हैं।

शीतला उपहार : पौधे 110-130 से.मी. ऊंचाई के होते हैं। फूल बुवाई के 38-40 दिन बाद चौथे एवं पॉचवें गांठ से आना शुरू हो जाते हैं। फल हरे 11-13 से.मी. लम्बाई के होते हैं। इस किस्म की औसत उपज 150-170 क्विंटल प्रति हेक्टर है। यह किस्म ऐलोवीन मोजेक विषाणु के प्रति अवरोधी हैं।

शीतला ज्योति : पौधे 110-150 से.मी. ऊँचाई के होते है। फूल बुवाई के 30-40 दिन बाद पौधे पॉचवें गांठ से आना शुरू हो जाते है। फल हरे 12-14 से.मी. लम्बाई के होते है। इस किस्म की औसत उपज 180-200 क्विंटल प्रति हेक्टर है। ऐलोवीन मोजेक विषाणु के प्रति अवरोधी है।

काशी भैरव : पौधे मध्यम ऊँचाई के 2-3 शाखाओं वाले होते हैं। फल गहरे रंग के 10-12 सें.मी. लम्बे होते है। इस किस्म की औसत उपज 200-220 क्विंटल प्रति हेक्टर है। यह किस्म ऐलोवीन मोजेक विषाणु के प्रति अवरोधी है।

काशी महिमा : इस किस्म के पौधे 130-170 से.मी. ऊँचाई के हाते हैं। फूल बुवाई के 36-40 दिन बाद चौथे-पॉचवे गांठ से आना शुरू हो जाते हैं। फल हरे 12-14 से.मी. लम्बे होते हैं। इस किस्म की औसत उपज 220-220 क्विंटल प्रति हेक्टर है। यह किस्म ऐलोवीन मोजेक विषाणु के प्रति अवरोधी है।

काशी लीला : यह किस्म भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी द्वारा विकसित की गई है। यह जल्दी पकने वाली किस्म है। प्रथम तुड़ाई बुआई के 35-40 दिन बाद संभव है। औसतन उपज 150-190 क्विंटल प्रति हेक्टर प्राप्त होती है। यह किस्म ऐलोवीन मोजेक वायरस एवं लीफकर्ल वायरस के प्रतिरोधी है।

काशी मोहिनी : यह किस्म भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी द्वारा विकसित की गई है। पौधा लम्बा और दोनों ऋतुओं के लिए उपयुक्त है। प्रथम तुड़ाई बुआई के 39-41 दिन बाद की जा सकती है। यह किस्म ग्रीष्म में उच्च तापमान सहन कर सकती है। यह किस्म ऐलोवीन मोजेक वायरस के प्रतिरोधी है।

काशी लालिमा : यह किस्म भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी से विकसित की गई है। इस किस्म के फल का रंग लाल होता है। यह येलो वीन मोजेक वायरस के प्रति सहनशील है।

मुर्गियों की सीआरडी बीमारी

• डॉ. पी.पी. सिंह • डॉ. सुखवीर सिंह
• श्रीमती रीना शर्मा • डॉ. स्वाती सिंह तोमर
• डॉ. जे.सी. गुप्ता
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्र, मुरैना

सीआरडी क्या है ?

सीआरडी मुर्गियों में श्वसन तंत्र को धीरे-धीरे प्रभावित करने वाली एक बीमारी होती है जो कि मुख्य रूप से माइकोप्लाज्मा गेलीसेप्टिकम नामक जीवाणु से होती है इस बीमारी में श्वसन तंत्र प्रभावित होने के कारण खांसना, छींकना, नाक से पानी बहना, ब्रायलर में वृद्धि दर कम होना तथा लेयर मुर्गियों में अंडा उत्पादन कम होना आदि लक्षण दिखाई देते हैं सीआरडी मुर्गियों में लंबे समय तक रहने वाली बीमारी होती है जो कि मुर्गियों के खराब प्रबंधन तथा तनाव आदि होने पर दिखाई देने लगती है।

मुर्गियों में सीआरडी प्रमुख एवं आर्थिक क्षति पहुंचाने वाली बीमारी है यह बीमारी मुख्य रूप से मुर्गियों के श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है जिसके कारण मुर्गियों में खांसी, नाक से पानी बहना तथा ब्रायलर मुर्गियों में कम वजन बढ़ना तथा लेयर मुर्गी में अंडा उत्पादन कम हो जाता है इस बीमारी के कारण न केवल मुर्गियों का स्वास्थ्य खराब होता है बल्कि इसके कारण एफसीआर खराब होना, कम अंडा उत्पादन तथा मृत्यु होने के कारण मुर्गी पालक किसानों को काफी आर्थिक हानि पहुंचती है

सीआरडी बीमारी सीसीआरडी से जुड़ी रहती है जो कि तब होती है जब माइकोप्लाज्मा गेलीसेप्टिकम संक्रमण के साथ ही द्वितीयक संक्रमण के रूप में ई कोलाई बैक्टीरिया का भी संक्रमण हो जाता है इन दोनों का संक्रमण होने पर मुर्गियों में अधिक घातक लक्षण जैसे एयर सेट में सूजन सेप्टीसीमिया और अधिक मृत्यु दर दिखाई देते हैं ब्रायलर मुर्गियां कमजोर एवं कम उत्पादन के कारण किसानों को बहुत अधिक आर्थिक नुकसान होता है इस कारण सीआरडी जब सीसीआरडी में बदल जाती है उस समय बीमारी को नियंत्रित करना और भी अधिक कठिन हो जाता है।

बीमारी का फैलाव

बीमारी का फैलाव हवा के द्वारा, प्रभावित मुर्गी द्वारा उत्पन्न अंडों से उत्पन्न चूजों में, प्रभावित मुर्गी से स्वस्थ मुर्गी में एवं प्रभावित मुर्गी के संपर्क के दाना, पानी, बर्तन, परिवहन वाहन तथा श्रमिक इत्यादि के माध्यम से फैलता है

बीमारी के लक्षण

इस बीमारी में मुर्गियों की नाक तथा आंख से पानी बहता है एवं आंख के पास सूजन दिखाई देती है प्रभावित मुर्गियों में कम भूख लगना, सुस्त रहना तथा शरीर भार कम हो जाता है लेयर मुर्गियों में अंडा उत्पादन कम हो जाता है इन लक्षणों के साथ ही खांसना, छींकना तथा सांस लेने में कठिनाई होने पर गले में विशेष आवाज सुनाई देना इत्यादि लक्षण दिखाई देते हैं बीमारी के इन लक्षणों की तीव्रता संक्रमण की मात्रा, द्वितीयक संक्रमण एवं वातावरणीय तनाव पर निर्भर करती है

बीमारी का उपचार

सीआरडी के उपचार हेतु एंटीबायोटिक जैसे टाइलोसिन, टेटरासाइक्लिन और टिल्मिकोसिन इत्यादि का उपयोग बैक्टीरिया लोड कम कर संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु किया जाता है स्वसन तंत्र को राहत देने वाली दवाइयां बीमारी के लक्षण को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती हैं इन्हें सहायक दवाइयों के रूप में उपयोग किया जाता है एंटीबायोटिक्स एवं श्वसन तंत्र में सहायता प्रदान करने वाली दवाइयों को उपयोग कर किसान सीआरडी का बेहतर प्रबंधन एवं नियंत्रण कर सकता है

बचाव हेतु प्रभावी रणनीति

सीआरडी से बचाव हेतु बाड़े में मुर्गियों की सतत निगरानी, जल्दी पहचान बीमारी को नियंत्रित करने एवं आर्थिक नुकसान कम करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं मुर्गियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में संतुलित पोषण व तनाव रहित प्रबंधन सर्वाधिक वांछनीय कारक होते हैं सीआरडी से बचाव हेतु टीकाकरण तथा चूजों की की खरीद माइकोप्लाज्मा संक्रमण से रहित प्रतिष्ठित हेचरी से करना महत्वपूर्ण साबित होते हैं सीआरडी की सतत निगरानी, जैव सुरक्षा उपायों का पूर्ण रूप से पालन एवं बाड़े में मुर्गियों का तनाव रहित प्रबंधन सीआरडी का नया संक्रमण व फैलाव रोकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सीआरडी बचाव के उपायों को अपना कर एवं संक्रमण की जल्दी पहचान कर सीआरडी को प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है।

वर्तमान समय में सीआरडी के प्रभावी नियंत्रण हेतु पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के साथ-साथ प्राकृतिक दवाओं का उपयोग करने से अधिक बेहतर परिणाम प्राप्त हुए हैं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में एंटीबायोटिक का प्रयोग, संक्रमण की सतत निगरानी, जैव सुरक्षा उपाय अपनाना तथा बेहतर प्रबंध उपाय अपनाकर संक्रमण तथा बीमारी का नियंत्रण किया जाता है प्राकृतिक दवाओं एवं एरोमेटिक तेलों के उपयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, सूजन में कमी तथा श्वसन मार्ग की सफाई होती है जिससे की सांस लेने में आसानी होती है और बीमारी के लक्षणों की तीव्रता में कमी आती है पारंपरिक चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक दवाओं का एक साथ प्रयोग करने से वह एक-दूसरे के पूरक की तरह कार्य करते हैं जिससे बीमारी का नियंत्रण बेहतर तरीके से होता है।

प्राकृतिक उपचार पद्धति

हाल के कुछ वर्षों में प्राकृतिक दवाओं के उपयोग द्वारा मुर्गियों में काफी स्वास्थ्य लाभ देखे गए हैं इनके उपयोग द्वारा न केवल मुर्गियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि देखी गई है बल्कि एंटीबायोटिक्स पर निर्भरता भी कम हुई है सीआरडी के उपचार में यूकेलिप्टस एवं पिपरमिंट के तेल उपयोग करने से काफी लाभ देखा गया है यूकेलिप्टस तेल के उपयोग से सूजन में कमी जीवाणुओं का नाश व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है जबकि पिपरमेंट का तेल संक्रमण के समय श्वसन मार्ग को साफ करने एवं मुर्गी को सांस लेने में राहत देने का कार्य करता है

ऑनलाईन सदस्यता के लिए लॉग इन करें
www.krishakjagat.org

धान-परती भूमि से समृद्धि की ओर

छत्तीसगढ़ में राई-सरसों खेती का उभरता अवसर

छत्तीसगढ़, जिसे 'मध्य भारत का धान का कटोरा' कहते हैं, अपनी कृषि अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार के रूप में खरीफ धान पर निर्भर रहा है। धान न केवल राज्य की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि सरकारी खरीद व्यवस्था के माध्यम से किसानों को स्थिर आय भी प्रदान करता है। हालांकि, धान की कटाई के बाद बड़ी मात्रा में कृषि भूमि परती रह जाती है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता और किसानों की आय बढ़ाने के अवसर सीमित हो जाते हैं। राई-सरसों जैसी तिलहन फसलें इस परती भूमि को उत्पादक बनाने में मदद कर सकती हैं।

धान परती भूमि को उत्पादक बनाने के लिए राई-सरसों की खेती अपनाना कई लाभ प्रदान कर सकता है, जैसे- ●किसानों की आय में वृद्धि ● फसल सघनता में सुधार ● खाद्य तेलों की आत्मनिर्भरता में योगदान ● टिकाऊ कृषि को बढ़ावा

इस तरह का बदलाव न केवल छत्तीसगढ़ की कृषि संरचना में सुधार करके और उपजाऊ बना सकता है, बल्कि पूरे भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। छत्तीसगढ़ का कुल कृषियोग्य क्षेत्र 4.78 मिलियन हेक्टेयर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 35% है। इस क्षेत्र का केवल 23% सिंचित है। यहाँ की प्रमुख मृदाएँ लाल और पीली हैं। राज्य में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 1,190 मिमी है, जिसमें से लगभग 88% वर्षा मानसून (मध्य जून से सितंबर) के दौरान होती है। राज्य की फसल सघनता लगभग 119% है और प्रमुख फसलों में धान, गेहूँ, मोटे अनाज, दलहन तथा तिलहन का उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ कृषि और जलवायु के दृष्टिकोण से तीन प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित है- ● छत्तीसगढ़ मैदानी क्षेत्र ● बस्तर पठार ● उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र

राज्य की जलवायु मुख्यतः शुष्क उप-आर्द्र प्रकृति की है, जिसमें मध्यम शीतकालीन तापमान और स्पष्ट मानसूनोत्तर मौसम देखा जाता है। यह जलवायु रबी तिलहन फसलों के लिए विशेष रूप से अनुकूल है, बशर्ते खरीफ मौसम के बाद मृदा में शेष नमी का संरक्षण और उचित कृषि तकनीकों का प्रभावी उपयोग किया जाए। इस प्रकार, धान कटाई के बाद खाली रह जाने वाली भूमि में राई-सरसों की खेती न केवल किसानों के लिए नई आय का स्रोत बन सकती है, बल्कि राज्य और देश की कृषि एवं खाद्य सुरक्षा रणनीति में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

धान का प्रभुत्व और परती भूमि की चुनौती

छग में लगभग 3.9 मिलियन हेक्टेयर में धान की खेती होती है, जो मुख्यतः वर्षा आधारित परिस्थितियों में ऊँचे भूभाग और निचले क्षेत्रों में फैली है। राज्य का धान उत्पादन लगभग 9.8 मिलियन टन है। खरीफ ऋतु में अधिक वर्षा और चिकनी मिट्टी के कारण धान का उत्पादन भरपूर होता है, लेकिन रबी में यही खेती सीमित रह जाती है। धान के कुल क्षेत्र का लगभग 32% भाग ही सिंचित है, जिससे कटाई के बाद लगभग 40-60% खेत परती रह जाते हैं, मुख्यतः वर्षा आधारित ऊँचे क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में।

भूमि के परती रहने के प्रमुख कारण हैं-

● मानसून के बाद मिट्टी की नमी का तेजी से कम हो जाना। ● निचले तल क्षेत्रों में जलभराव की समस्या। ● लंबी अवधि वाली धान किस्मों की देर से कटाई ● अल्पावधि वाली किस्मों तिलहन व दलहन के बीजो की कमी ● आवारा पशुओं द्वारा नुकसान ● किसानों की सीमित तकनीकी जानकारी और जोखिम न ले पाना

यह अनुमान है कि, खरीफ धान क्षेत्र का लगभग 50% भाग रबी मौसम में परती रह जाता है, जो की फसल विविधीकरण के लिए बहुत अच्छा है।

राई-सरसों : धान परती भूमि के लिए रणनीतिक विकल्प

रबी फसलों में राई-सरसों धान परती भूमि के लिए सबसे उपयुक्त फसल के रूप में उभर रही है। क्योंकि इसे कम पानी में उगाया जा सकता है, अल्प अवधि में पक जाती है और विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में अनुकूलन क्षमता रखती है। भारत में राई-सरसों देश की सबसे महत्वपूर्ण तिलहन फसलों में से एक है, जो कुल तिलहन क्षेत्रफल का 30% है, और कुल उत्पादन का 33% योगदान देती है। वर्ष 2023-24 में भारत में इसका उत्पादन लगभग 13.2 मिलियन टन रहा, जिससे यह देश की मुख्य तिलहन फसल बन गई राई-सरसों की कई जैविक और कृषि संबंधी विशेषताएँ इसे छत्तीसगढ़ के धान परती भूमि के लिए आदर्श बनाती हैं-

राई-सरसों की विशेषताएँ

मृदा की शेष नमी का कुशल उपयोग- सरसों बिना सिंचाई या सीमित नमी में भी उगाई जा सकती है।

कम अवधि की फसल- अधिकांश किस्में 90-120 दिनों में पकती हैं। जो धान की कटाई के बाद उपयुक्त है।

जलवायु सहनशीलता- सरसों मध्यम सूखे और तापमान में उतार-चढ़ाव सहन कर सकती है।

बाजार मांग- सरसों का तेल पूर्वी और मध्य भारत में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जिससे तेल की स्थिर मांग और मूल्य स्थिरता बनी रहती है।

राई-सरसों छत्तीसगढ़ की धान-परती पारिस्थितिकी के लिए अत्यंत उपयुक्त फसल है। फसल बुवाई की अवधि नवंबर के दुसरे पखवाड़े से लेकर दिसंबर के पहले सप्ताह तक होती है, जो 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड के अनुकूलित शीतकालीन तापमान के लिए उपयुक्त है। यह तापमान राई-सरसों तथा तोरिया की वृद्धि और विकास के लिए आदर्श है। कम पानी और कम लागत वाली फसल होने के कारण राई-सरसों को अन्य अनाज फसलों की तुलना में बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे धान की कटाई के तुरंत बाद शून्य जुताई (जीरो टिलेज) या न्यूनतम जुताई के साथ सफलतापूर्वक बोया जा सकता है। इसकी 90-120 दिनों की अल्प अवधि इसे खरीफ के बाद नमी रहित या कम नमी वाले खेतों में बिना फसल चक्र को प्रभावित किए आसानी से समायोजित होने की सुविधा देती है। इसके अतिरिक्त, चना के साथ एकल या मिश्रित फसल के रूप इसका उत्पादन संभव है।

आर्थिक दृष्टि से भी राई-सरसों किसानों के लिए स्पष्ट लाभ प्रदान करती है। इसकी खेती की लागत अपेक्षाकृत कम है और आकर्षक न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से मूल्य समर्थन सुनिश्चित होता है। वर्तमान में राज्य में राई-सरसों का सीमित क्षेत्रफल लगभग 31,000 हेक्टेयर है, जिसमें लगभग 17,260 टन उत्पादन और 563 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता दर्ज की गई है। राई-सरसों की लाभप्रदता और अनुकूलन क्षमता धान-परती क्षेत्रों में इसके व्यापक विस्तार की प्रबल संभावनाओं को दर्शाती है। अनुसंधान परीक्षणों से यह सिद्ध हुआ है कि उन्नत राई-सरसों उत्पादन तकनीकों को अपनाने से पारंपरिक किसान पद्धतियों की तुलना में धान-परती परिस्थितियों में 20% से अधिक उपज वृद्धि संभव है।

उपयुक्त किस्में

किस्म	अधिसूचना वर्ष	परिपक्वता (दिन)	औसत उपज (किग्रा/हे.)	तेल (%)
छत्तीसगढ़ सरसों	2010	120	1150	39
टीबीएम-209	2019	112	1650	41
एनआरसीएचबी-101	2009	115	1450	40
डीआरएमआर 150-35	2020	110	1500	40
बीबीएम-1	2022	115	1600	41

खाद्य तेल उद्योगों को प्रोत्साहन

धान- परती क्षेत्रों में राई-सरसों के विस्तार से स्थानीय तेल प्रसंस्करण उद्योगों के लिए मजबूत मांग उत्पन्न होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और मध्यम स्तर के ऑयल एक्सपेलर एवं रिफाइनिंग इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय मूल्य श्रृंखलाओं (वैल्यू चेन) के विकास से ग्रामीण उद्यमिता और कृषि-औद्योगिक प्रगति को नई गति मिल सकती है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भूमिका

अखिल भारतीय समन्वित राई-सरसों अनुसंधान परियोजना- (AICRP-RM) के माध्यम से उच्च उत्पादकता एवं रोग-प्रतिरोधी किस्मों के विकास और प्रसार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही, धान-परती क्षेत्रों के लिए उपयुक्त शून्य जुताई (ज़ीरो टिलेज) तकनीकों को बढ़ावा देने के साथ विविध कृषि-पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुरूप जलवायु-सहिष्णु किस्मों की पहचान करके उत्पादन को बढाना आईसीएआर के प्रमुख उद्देश्य हैं।इन प्रयासों को अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन (फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन) और व्यापक किसान प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा सुदृढ़ किया जाता है, ताकि खेत स्तर पर तकनीकों को शीघ्र अपनाया जा सके। साथ ही AICRP-RM के अंतर्गत छत्तीसगढ़ (कृषि-जलवायु क्षेत्र–V) के लिए देरी से बुवाई की परिस्थितियों में उपयुक्त तथा उच्च उत्पादन एवं उत्पादकता वाली विभिन्न किस्मों का विकास किया गया है।

आईसीएआर-राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान, रायपुर की पहल

धान-परती भूमि को उत्पादक बनाने की दिशा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान-राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान, रायपुर ने वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्थागत हस्तक्षेपों के माध्यम से उल्लेखनीय पहल की है। विशेष रूप से एससीएसपी (SCSP) और टीएसपी (TSP) योजनाओं के अंतर्गत आयोजित प्रदर्शनों ने यह सिद्ध किया है कि राई-सरसों की उन्नत किस्में धान-परती क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयुक्त और लाभकारी विकल्प बन सकती हैं। आईसीएआर-एनआईबीएसएम ने पिछले तीन वर्षों से संस्थान में खेत-स्तर पर संभावित राई-सरसों किस्मों का व्यवस्थित मूल्यांकन किया गया। इन परीक्षणों में डीआरएमआर-150-35 किस्म ने अत्यंत उत्साहजनक परिणाम दिए।यह किस्म 95-110 दिनों में परिपक्व हो जाती है, जिससे धान की कटाई के बाद मध्य नवंबर से दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक इसकी बुवाई सहजता से की जा सकती है।

विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह रहा कि एफिड (चैंपा) को छोड़कर प्रमुख कीट एवं रोगों का कोई गंभीर प्रकोप नहीं देखा गया। यह इसकी जैविक तनाव सहनशीलता और स्थानीय परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किस्मों को अपनाकर किसान कम जोखिम में बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।

आर्थिक लाभ और आजीविका सुरक्षा

धान-परती क्षेत्रों में राई-सरसों को शामिल करने से किसानों की आय और आजीविका सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है। वर्षा आधारित धान पारिस्थितिकी तंत्र में किए गए प्रदर्शनों से यह सिद्ध हुआ है कि शून्य जुताई प्रणाली के अंतर्गत राई-सरसों की खेती से 8-14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त की जा सकती है। अल्प अवधि में प्रति हेक्टेयर रु. 27,000 से अधिक का शुद्ध लाभ अर्जित किया जा सकता है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए, जो खरीफ फसल पर निर्भर रहते हैं, राई-सरसों की खेती कई दृष्टियों से लाभकारी सिद्ध हो रही है- ● रबी मौसम में अतिरिक्त आय का स्रोत ● फसल प्रणाली का विविधीकरण ● ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर ● फसल विफलता की स्थिति में वित्तीय जोखिम में कमी

आईसीएआर-राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान के निदेशक एवं पूर्व निदेशक, आईसीएआर-भारतीय राई-सरसों अनुसंधान संस्थान, डॉ. पी. के. राय तथा संयुक्त निदेशक डॉ. पंकज शर्मा, जो असम में राई-सरसों क्षेत्र विस्तार हेतु विश्व बैंक समर्थित असम एग्रीबिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट (APART) के सफल क्रियान्वयन में मुख्य सलाहकार एवं प्रमुख विशेषज्ञ के रूप में सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं, ने बल देकर कहा कि छत्तीसगढ़ के धान-परती क्षेत्रों में राई-सरसों की खेती को उन्नत किस्मों के व्यापक प्रसार, शून्य जुताई एवं नमी संरक्षण तकनीकों के प्रोत्साहन से तथा समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के माध्यम से बड़े स्तर पर विस्तारित किया जा सकता है।

प्रस्तुति : डॉ. पंकज शर्मा,
राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान, रायपुर

मधुमक्खी पालन

धान-परती क्षेत्रों में राई-सरसों की खेती के विस्तार से मधुमक्खी पालन के लिए एक मजबूत आधार तैयार होगा, क्योंकि ये फसलें रबी मौसम में अच्छा नेक्टर और परागकण प्रदान करती हैं। इससे सहायक उद्यम के रूप में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा मिलेगा, जो ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और छोटे किसानों के लिए रोजगार सृजित करेगा। परागण में वृद्धि से फसलों की उपज और गुणवत्ता में भी सुधार होगा। यह एक समग्र प्रणाली न केवल आजीविका को सुदृढ़ करेगी, बल्कि पारिस्थितिकीय स्थिरता को भी समर्थन देगी।

5 संकल्पों के साथ मनाया केन्द्रीय कृषि मंत्री ने जन्मदिन

भोपाल (कृषक जगत)। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 67 साल के हो गए हैं। उन्होंने अपना जन्मदिन 'प्रेम-सेवा संकल्प दिवस' के तौर पर मनाया। जिसके तहत वे राज्य में अलग-अलग जगहों पर कोचिंग क्लास और मोबाइल हॉस्पिटल लॉन्च करेंगे। श्री चौहान लोगों के बीच मामा के नाम से पॉपुलर हैं, और उनके जन्मदिन पर लॉन्च होने वाली कोचिंग क्लास और हॉस्पिटल के नाम में यही नाम होगा। श्री शिवराज सिंह पर्यावरण, सेवा, सहायता, शिक्षा और टैलेंट प्रमोशन पर केंद्रित पांच संकल्प लेंगे।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, 'अपने माता-पिता की याद में उन्होंने 'प्रेम-सुंदर प्रतिभा सम्मान' अवॉर्ड शुरू करने का फैसला किया है।

गत 5 मार्च को केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के 67वें जन्मदिन पर भोपाल स्थित निवास पर उन्हें कृषक जगत का ताजा अंक भेंट करते हुए प्रकाश दुबे

विदिशा लोकसभा सीट के सभी आठ असेंबली एरिया में, क्लास 10 और 12 के टॉपर्स को रु. 51,000, रु. 31,000 और रु. 21,000 के कैश प्राइज मिलेंगे। पार्लियामेंट्री एरिया में, टॉप तीन रैंक होल्डर्स को स्पेशल अवॉर्ड मिलेंगे।

श्री चौहान गांव की हेल्थकेयर सर्विस को मजबूत करने के लिए विदिशा की सभी आठ असेंबली एरिया में 'मामा चलित हॉस्पिटल' भी लॉन्च करेंगे। इन गाड़ियों में मॉडर्न डायग्नोस्टिक सुविधाएं और क्वालिफाइड डॉक्टर होंगे जो गांवों और बस्तियों में फ्री इलाज और कंसल्टेशन देंगे।

इस मौके पर विदिशा शहर, रायसेन और भैरुंदा में 'मामा कोचिंग क्लासेस' लॉन्च की जाएंगी।

उद्यानिकी सचिव ने किया नर्सरी का निरीक्षण

सीहोर (कृषक जगत)। उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग के सचिव श्री जॉन किंग्सली ए.आर. एवं विभाग के आयुक्त श्री अरविंद कुमार दुबे ने सीहोर जिले के श्यामपुर स्थित शासकीय मॉडल रोपणी एवं नर्सरी पर निर्मित प्लास्टिक लाइनिंग ऑफ फार्म पौण्ड का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान सचिव श्री जॉन किंग्सली ए.आर. ने श्यामपुर नर्सरी को प्रशिक्षण फार्म के रूप में विकसित करने के निर्देश दिये, ताकि किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त हो सके और उद्यानिकी को बढ़ावा मिले। उन्होंने ग्राम घाटपलासी में प्रगतिशील किसान श्री श्याम मीणा द्वारा 5 एकड़ भूमि में की जा रही अमरूद की खेती का भी निरीक्षण किया। इस दौरान जानकारी दी गई कि किसान श्री मीणा द्वारा उद्यानिकी विभाग के मार्गदर्शन में 5 एकड़ में अमरूद की अल्ट्रा हाई डेंसिटी वाली 'थाई पिंक' किस्म का अमरूद का बगीचा लगाया गया है। निरीक्षण के दौरान अपर संचालक डॉ. कमल सिंह किरार, संयुक्त संचालक श्रीमती जयमाला सिंह, संचालनालय नर्सरी शाखा प्रभारी श्री दीनानाथ धोटे, सहायक संचालक श्री जगदीश मुजाल्दा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

प्रदेश में तीसरी फसल लेने की तैयारी

11 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में ली जाएगी मूंग

(अतुल सक्सेना)

भोपाल (कृषक जगत)। प्रदेश में रबी फसलें पककर तैयार हैं। कुछ स्थानों पर कटाई भी प्रारंभ हो गई है। इस बीच किसानों ने तीसरी फसल लेने की तैयारी शुरू कर दी है।

राज्य में तीसरी फसल के रूप में सबसे अधिक क्षेत्र में मूंग लगाई जाती है। जिसकी बुवाई खाली पड़े खेतों में शुरू हो रही है। इस वर्ष लगभग 15 लाख हेक्टेयर में जायद फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रदेश के कृषि विभाग ने जायद वर्ष 2026 के लिए फसलों के लक्ष्य तय कर दिए हैं। जायद में मुख्य रूप से मूंग, उड़द, मक्का, मूंगफली एवं धान ली जाती है। इसमें सबसे अधिक रकबा मूंग का होता है। इस वर्ष लगभग 11 लाख 29 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में मूंग लेने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 1.75 लाख हेक्टेयर में उड़द, 19 हजार हेक्टेयर में मक्का, 30 हजार हेक्टेयर में मूंगफली एवं 46 हजार हेक्टेयर में धान लेने की तैयारी की गई है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के नर्मदापुरम संभाग में सबसे अधिक मूंग फसल ली जाती है। इस वर्ष भी नर्मदापुरम संभाग में लगभग 4.27 लाख हेक्टेयर में मूंग फसल लेने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं शहडोल संभाग में सबसे कम मात्र 200 हेक्टेयर में मूंग फसल लेने का लक्ष्य है। इसी प्रकार भोपाल संभाग में 2.72 लाख हे., जबलपुर संभाग में 2.47 लाख हे., इंदौर संभाग में लगभग 72 हजार हे. एवं सागर संभाग में लगभग 48 हजार हे. में मूंग लगाई जाएगी।

म.प्र. में जायद फसलों के लक्ष्य 2026
(हेक्टेयर में)

फसल	लक्ष्य 2026	गत वर्ष 2025 की बुवाई
मूंग	11,29,631	14,35000
उड़द	1,75,455	95,000
मक्का	19,294	27,000
मूंगफली	30,458	19,000
धान	46,010	51,000

वैसे सभी जायद फसलों को देखें तो प्रदेश में सबसे अधिक नर्मदापुरम संभाग में 4.61 लाख हेक्टेयर में, जबलपुर में 3.77 लाख हे., भोपाल में 2.80 लाख हे., इंदौर में 92 हजार हे., सागर में 87 हजार हे. एवं उज्जैन संभाग में 46 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में जायद फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है।

इधर राज्य सरकार ने उड़द पर 600 रुपए क्विंटल बोनस घोषित कर कृषकों को आकर्षित करने की योजना बनाई है। इसे दलहन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का एक कदम माना जा रहा है। जायद में उड़द का क्षेत्र लगभग 1.75 लाख हे. तय किया गया है, जबकि गत वर्ष 2025 में उड़द की बोनी 95 हजार हेक्टेयर में हुई थी।

फोटो गैलरी

भगोरिया

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जनजाति लोक उत्सव भगोरिया पर्व के अंतिम भगोरिया में बड़वानी जिले के जुलवानिया में उल्लासपूर्वक शामिल हुए।

लोकार्पण

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़वानी के नागलवाड़ी में भीलट देव व्याख्यान केंद्र का लोकार्पण किया।

लहलहाता गेहूं

नर्मदापुरम जिले की माखननगर तहसील के प्रगतिशील किसान श्री श्रवण मीना ने अपनी 12 एकड़ जमीन में गेहूं की किस्म जीडब्ल्यू 513 लगाई है। फसल की वर्तमान अवस्था को देखते हुए लगभग 24-25 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन प्राप्त होने की संभावना है।

कृषि उपसंचालक-सहायक संचालकों के तबादले

भोपाल (कृषक जगत)। राज्य शासन ने कृषि संचालनालय में पदस्थ उपसंचालक एवं सहायक संचालक स्तर के अधिकारियों को धन-धान्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिलों में पदस्थ किया है।

आदेश के मुताबिक समस्त अधिकारियों को संचालनालय से स्थानान्तरित किया गया है- इसमें श्री संजय दोषी को उपसंचालक डिण्डोरी, श्री अवनीश चतुर्वेदी को उपसंचालक अनूपपुर, श्री आर.एस. गुप्ता को उपसंचालक सीधी, श्री हरीश मालवीय को उपसंचालक निवाड़ी, श्री के.एस. यादव को उपसंचालक शहडोल एवं श्री आर. पी.एस. नायक को परियोजना संचालक आत्मा डिण्डोरी पदस्थ किया गया है। इसी प्रकार सहायक संचालकों में सर्वश्री गोपाल पाटीदार को शहडोल, श्याम यदुवंशी को निवाड़ी, सतेन्द्र सिंह रघुवंशी को सीधी, बसंत कुमार माण्डेर को अनूपपुर, रवि कुमार अमिलयार को टीकमगढ़, रेहम डॉवर को अलीराजपुर, कृष्ण कुमार बड़वाया को डिण्डोरी एवं कुलदीप शर्मा को उमरिया उपसंचालक कार्यालय में पदस्थ किया गया है।

ऑनलाईन सदस्यता के लिए लॉग इन करें
www.krishakjagat.org

कृषि मेले में विभागीय स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहा

सिवनी

सिवनी (कृषक जगत)। कृषि विभाग आत्मा अंतर्गत कृषि मेले में शासकीय विभागों के स्टाल आकर्षण का केंद्र रहे। विभागों में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य, ग्रामीण आजीविका मिशन सहित विभिन्न विभागों के स्टॉल पर किसानों को दी जाने वाली योजनाओं के अलावा प्राकृतिक खेती, जैविक उत्पादन, पराली प्रबंधन, फार्मर रजिस्ट्री, ई-विकास प्रणाली, उन्नत बीज, उर्वरक एवं आधुनिक कृषि यंत्रों की जानकारी दी गई। कृषि वैज्ञानिकों ने परिचर्चा के माध्यम से किसानों की समस्याओं का समाधान किया, वहीं जैविक एवं प्राकृतिक हाट बाजार आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा विभिन्न योजनाओं के हितलाभ के वितरण के साथ ही स्टॉल का अवलोकन किया। मेले में सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, पूर्व सांसद श्री ढालसिंह बिसेन, विधायक श्री दिनेश राय, श्री कमल मर्सकोले,जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मालती डेहरिया, जिला भाजपा अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन, पूर्व विधायक श्री राकेश पाल,कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले,उप संचालक कृषि श्री एसके धुर्वे, सहायक संचालक कृषि श्री राजेश मेश्राम, श्री पवन कौरव, श्री प्रफुल्ल घोड़ेश्वर, श्री नितिन गनवीर, डॉ. अखिलेश कुल्हाड़े, श्री नरेश उइके, श्री ऋषिकेश चन्द्रपुरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी उपस्थित थे।

शिवपुरी को नरवाई विहीन जिला बनाना है : श्री चौधरी

शिवपुरी

शिवपुरी (कृषक जगत)। कलेक्टर श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में गत दिनों जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में कम्बाईन हार्वेस्टर मालिक/संचालकों, बड़े एवं उन्नतशील कृषकों तथा कृषक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नरवाई न जलाने हेतु एवं कम्बाईन हार्वेस्टर से गेहूं फसल कटाई उपरान्त शेष फसल अवशेष का स्ट्रारीपर से भूसा बनाकर निपटान करने की समझाईश दी गई।

कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि शिवपुरी जिले को नरवाई विहीन जिला बनाना है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन कर कृषकों को पराली न जलाने के संबंध में जागरूक करना होगा। नरवाई जलाने की घटनाएं सैटेलाइट द्वारा प्रदर्शित होती है।

इस अवसर पर अपर कलेक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला, प्रबंधक उद्योग विभाग अरविंद महेश्वरी, उप संचालक कृषि पान सिंह करौरिया, सहायक संचालक कृषि, सहायक कृषि यंत्री, समस्त विकासखंडों के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं अन्य अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ कृषक संगठन के प्रतिनिधि श्री धाकड तथा लगभग-75 कम्बाईन हार्वेस्टर मालिक अथवा संचालक एवं कृषक उपस्थित थे।

उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग की योजनाएं

मसाला क्षेत्र विस्तार

प्रजोक्ट : मसाला क्षेत्र विस्तार

उद्देश्य : बागवानी उत्पादन की उन्नति, कृषक संख्या में वृद्धि, आमदनी और पोषाहार सुरक्षा को बढ़ावा देना। गुणवत्ता युक्त पौध सामग्री का उपयोग करते हुए उत्पादकता में सुधार लाना। बागवानी अनुसंधान, तकनीकी को बढ़ावा, विस्तारीकरण, फसलोत्तर प्रबंधन, प्रसंस्करण एवं विपणन आदि को बढ़ावा देना। कृषकों को आमदनी का स्थाई स्त्रोत उपलब्ध कराना। रोज़गार के नवीन अवसरों का सृजन करना। उत्पादन एवं प्रसंस्करण को बढ़ाकर उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर बाजार में उद्यानिकी उत्पादों की उपलब्धता बनाए रखना।

कार्यक्षेत्र : जिला-कटनी, सिवनी, बालाघाट, नरसिंहपुर, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, श्योपुर, शिवपुरी, मुरैना एवं भिण्ड।

चयनित फसलें : बीजीय मसाला फसल यथा धनिया, मेथी, अजवाइन, सोआ, कलौंजी, सौंफ, जीरा, बिलायती सौंफ, अजमोद, स्याह जीरा तथा प्रकंदी मसाला फसलें लहसुन, हल्दी, अदरक।

स्वरूप : परियोजना अंतर्गत निर्धारित इकाई लागत राशि 30 हजार रुपए तक 40 प्रतिशत तक अनुदान राशि 12000 देय है।

कृषक की पात्रता : सभी वर्ग के कृषक।

अनुदान की पात्रता : निर्धारित इकाई लागत पर 40 प्रतिशत अनुदाय देय है।

सम्पर्क : जिले के उप/सहयक संचालक उद्यान विकासखंड स्तर पर व.उ.वि.अधि/ ग्रा.उ.वि.अधि.।

स्त्रोत : जनसंपर्क विभाग म.प्र. के प्रकाशन 'नई राहें नए अवसर' से उद्धृत।

टिकाऊ और उत्पादक कृषि प्रणाली सुनिश्चित करने की आवश्यकता : डॉ. बिस्वास

जनेकृविवि में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु नवीन उर्वरक प्रौद्योगिकियों पर व्याख्यान

जबलपुर

जबलपुर (कृषक जगत)। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के कुलपति डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा की प्रेरणा से मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायनशास्त्र विभाग के अंतर्गत एडवांस्ड फैकल्टी ट्रेनिंग सेंटर जबलपुर द्वारा 'सतत खेती में मिट्टी के स्वास्थ्य के प्रबंधन के लिए उभरती प्रौद्योगिकियां और नवाचार' विषय पर आयोजित 21 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण के 20वें दिन टिकाऊ कृषि और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नईदिल्ली के प्रख्यात मृदा वैज्ञानिक डॉ. डी. आर. बिस्वास, एमेरिटस साइंटिस्ट द्वारा 'सतत खेती में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु नवीन उर्वरक फार्मूलेशन' विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। डॉ. बिस्वास ने बताया कि एक चम्मच मिट्टी में अरबों सूक्ष्मजीव उपस्थित रहते हैं, जो मृदा को जीवंत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

डॉ. बिस्वास ने बताया कि 1 किलोग्राम एनपीके उर्वरक के प्रयोग से औसतन 3.5 किलोग्राम अनाज उत्पादन प्राप्त होता है, किंतु पोषक तत्व उपयोग दक्षता अभी भी संतोषजनक नहीं है। पोटाश उपयोग दक्षता लगभग 60-70 %, नाइट्रोजन उपयोग दक्षता 30-50%, फॉस्फोरस उपयोग दक्षता 15-20% तथा सूक्ष्म पोषक तत्व उपयोग दक्षता मात्र 2-5% है।

कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष डॉ. बी.के. दीक्षित, डॉ.बी.एस.द्विवेदी, डॉ. जी.एस.टैगोर, डॉ. अमित उपाध्याय, डॉ. आर.के.साहू, डॉ. एफसी अमूले, डॉ. अभिषेक शर्मा, सर्वश्री प्रशांत कुर्मी, मधुकर, श्रीमती संगीता ठाकुर, रविन्द्र कुमार, धर्मेन्द्र विजयवर्गीय, विकास पटेल, श्रीमती रचना यादव, राजकुमार काछी सहित प्रशिक्षाणार्थी उपस्थित रहे।

मसाला फसलों की उन्नत खेती से बढ़ेगी किसानों की आय

जबलपुर (कृषक जगत)। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के कुलपति डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा की प्रेरणा से उद्यान शास्त्र विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी विकास परियोजना के अंतर्गत विकासखंड पनागर के ग्राम डूंगरिया में अधिष्ठाता उद्यानिकी संकाय डॉ. स्वाती बारचे के मुख्यातिथ्य में कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान डॉ. बारचे ने कहा कि मसाला फसलों की उन्नत खेती से किसानों की आय बढ़ेगी। डॉ. बारचे ने मसालावर्गीय फसलों की उन्नत उत्पादन तकनीकों की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर परियोजना अधिकारी डॉ. रजनी शर्मा, सहायक प्राध्यापक डॉ. अमित झा एवं डॉ. रीना नायर, कृषि विज्ञान केन्द्र, जबलपुर के वैज्ञानिक डॉ. प्रमोद गुप्ता तथा कृषि विस्तार अधिकारी श्रीमती मोनिका झा सहित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

कामयाब किसान की कहानी

मधुबाला को गुलाब की खेती से हो रही लाखों की कमाई

रतलाम

रतलाम (कृषक जगत)। जिले के कुशगढ़-पिपलोदा की रहने वाली महिला किसान मधुबाला पाटीदार ने पॉलीहाउस तकनीक अपनाकर गुलाब की खेती से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। उन्होंने 2 बीघा भूमि में पॉलीहाउस स्थापित कर गुलाब के फूलों की खेती शुरू की, जिससे उन्हें सालाना लगभग 25 लाख रुपये की आमदनी हो रही है। इसमें से मजदूरी एवं अन्य खर्च निकालने के बाद उन्हें 12 से 13 लाख रुपये का शुद्ध मुनाफा प्राप्त होता है।

मधुबाला ने बताया कि उनके द्वारा उत्पादित गुलाब रतलाम के अलावा भोपाल और दिल्ली तक बेचे जाते हैं, जिससे उन्हें बेहतर बाजार मूल्य मिलता है। उन्होंने बताया कि उन्हें पॉलीहाउस में खेती की जानकारी उन्हें उद्यानिकी विभाग के माध्यम से प्राप्त हुई तथा सरकारी योजना के अंतर्गत पॉलीहाउस निर्माण के लिए आर्थिक सहायता भी मिली।

गुलाब की खेती में सफलता मिलने के बाद उन्होंने अपने खेत का विस्तार करते हुए 15 से 16 बीघा क्षेत्र में पॉलीहाउस स्थापित कर ककड़ी एवं गुलाब की खेती शुरू की। मधुबाला ने बताया कि पहले वे पारंपरिक फसलें जैसे सोयाबीन, चना और गेहूं की खेती करती थी, जिसमें प्रति बीघा मात्र 2 क्विंटल सोयाबीन का उत्पादन होता था। इससे मजदूरी का खर्च निकालना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन पॉलीहाउस तकनीक अपनाने से उनकी आमदनी में कई गुना वृद्धि हुई है।

समस्या – गुड़मार की खेती कैसे करें?

समाधान – गुड़मार अथवा मधुनाशिनी यह वनौषधि अधिकतर उद्यानों में लगाई जाती है। यह एक रोमश काष्ठमयलता है इसके पत्ते नोकदार तथा मृदु रोमश होते हैं। पुष्प छोटे–छोटे पीले रंग के होते हैं। इसकी जड़ उपयोगी है। यह वनौषधि वनों में प्राकृतिक रूप से काफी मात्रा में मिलती है। इसकी खेती बीजों द्वारा या कलमों द्वारा की जाती है। बीजों द्वारा पॉली पैक में इसकी पौध नर्सरी विकसित कर लगाते हैं। फरवरी–मार्च में विकसित पौध का प्रत्यारोपण विधिवत खेत में करें। वर्षाकाल में यह लता विकसित होकर खूब फलने–फूलने लगती है इसकी जड़ों का उपयोग खांसी, हृदयरोग आदि में किया जाता है।

समस्या – मेरी लगाई हल्दी की पत्तियां सूख रही हैं। चौड़ी और संकरी पत्ती वाले खरपतवार बहुत उग आए हैं। कृपया निदान करें।

समाधान – किसान भाई हल्दी के पौधे की पत्तियां सूखने के कई कारण हो सकते हैं जैसे दीमक का प्रकोप या किसी पोषक तत्व की कमी पाई जाना या किसी बीमारी का प्रकोप। अत: आप किसी कीट विशेषज्ञ से सम्पर्क करें तथा अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण करवायें। खरपतवार नियंत्रण के लिए पैन्डीमिथालीन,

एट्राजिन या एलाक्लोर दवाई का बुवाई के एक से दो दिन बाद 1.00 किग्रा. प्रति हेक्टेयर शुद्ध मात्रा को लेकर 500 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर में घोल बनाकर फसल तथा खरपतवार दोनों के उगने से पहले छिड़काव करके खरपतवारों का नियंत्रण प्रभावशाली ढंग से कर सकते हैं।

समस्या – ट्रैक्टर का समुचित उपयोग करने के लिए ट्रेनिंग कहां मिलेगी?

समाधान – भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि अभियांत्रिकी संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से भी ट्रेनिंग मिल सकती है। भारत सरकार के ट्रेनिंग सेंटर बुधनी (मध्य प्रदेश), हिसार (हरियाणा), अनन्तपुर (तेलंगाना), विश्वनाथ चेरियाल (आन्ध्र प्रदेश) एवं आसाम में उपलब्ध है इसके अतिरिक्त आप विभिन्न कृषि विद्यालयों से भी सम्पर्क कर सकते हैं।

समस्या – मैं 3 तीन एकड़ का काश्तकार हूं, खेती का काम करने के लिए उपयुक्त ट्रैक्टर बताएं।

समाधान – ट्रैक्टर का चुनाव जमीन की किस्म, खेत का क्षेत्रफल तथा फसल के घनत्व पर निर्भर करता है। 3 एकड़ भूमि के लिये, उपलब्ध ट्रैक्टरों में कोई भी आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं होगा। अत: आप किराये पर ट्रैक्टर लेकर खेती कार्य करें ।

समस्या – धान में नील हरित शैवाल (बीजीए) का उपयोग किस प्रकार करें।

समाधान – धान की खेती में नील हरित शैवाल टीके का प्रयोग लाभकारी पाया गया है। इस टीके के प्रयोग के बाद धान के खेत में लगभग 10 दिन तक पानी भरा रहने दें। जिससे खेत में शैवाल की अच्छी बढ़ोतरी हो सके। इस टीके का कम से कम लगातार 2–4 फसल मौसम में अनुमोदित फॉस्फोरस की उचित मात्रा के साथ प्रयोग करें। यदि रसायनिक खाद का प्रयोग न किया जाए तो नील हरित शैवाल के टीके से 20–30 किग्रा. नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर का लाभ होता है।

समस्या– मैंने एम.पी. चरी के बारे में पढ़ा था जायद में चारे के लिये उपयोगी है, कृपया विस्तार से बतायें।

समाधान– आपने ठीक ही सुना था जायद मौसम में हरे चारे की कमी प्राय: सभी जगह होती है और यदि हरा चारा उपलब्ध हो जाये तो पशुओं के लिये विशेषकर दुधारू पशुओं को बहुत लाभ मिलता है और अच्छे दूध उत्पादन का लाभ पालकों को भी मिलता है कुछ ना कुछ क्षेत्र में एमपी चरी को लगाकर ग्रीष्मकाल में हरा चारा उपलब्ध कराया जा सकता है। इसे लगाने के निम्न फायदे हैं।

- क्योंकि इसमें एच.सी. एन. नामक जहरीला पदार्थ बहुत कम होता है जिससे पशुओं को बचाया जा सकता है।
- इसमें 5–6 प्रतिशत प्रोटीन होता है। इसका तना पतला और मुलायम होता है जिसे पशु चाव से खाते और पचाते हैं।
- एक हेक्टर क्षेत्र में 40 किलो बीज लगता है।
- यूरिया 260 किलो, 350 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 33 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश डालें।
- यूरिया की आधी मात्रा, फास्फेट–पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय दें शेष यूरिया को दो भागों में पहली कटाई के बाद और दूसरी कटाई के बाद दिया जाये।

समस्या– मैं जायद में मूंगफली लगाना चाहता हूं कब तक लगाना चाहिये, कृपया तकनीकी बतायें।

समाधान– जायद की मूंगफली खरीफ की तुलना में अधिक उत्पादन देने की क्षमता रखती है क्योंकि उसे भरपूर प्रकाश तथा वातावरण मिलता है परंतु अब उसे लगाने का समय करीब–करीब समाप्त हो रहा है। जायद की मूंगफली पर विस्तार से सामग्री का प्रकाशन हो चुका है आपने पढ़ा भी होगा। फिर भी आपकी जिज्ञासा हेतु उत्पादन के प्रमुख बिन्दुओं का प्रकाशन किया जा रहा है।

- उन्नत जातियां जैसे डी.एच.86, आर. 8808 प्रमुख हैं।
- बीज दर 90–100 किलो/हे. की दर से डाला जाये।
- उर्वरकों में 40 किलो यूरिया, 250 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 60 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश/हे., इसके अलावा गोबर की खाद डालने से अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।
- बुआई का उचित समय फरवरी के आखिरी सप्ताह से मार्च का प्रथम सप्ताह।
- बीजोपचार 2 ग्राम थाईरम प्रति किलो बीज का करें। इसके अलावा राइजोबियम कल्चर 5 ग्राम/किलो बीज द्वारा भी किया जाये।
- सिंचाई प्रत्येक सप्ताह में एक बार जरूरी है वो भी खरपतवार निकालने के बाद।।

निवेदन

समस्या-समाधान स्तंभ में पाठकों से निवेदन है कि अपनी खेती-किसानी संबंधी समस्या कृषि विशेषज्ञों से निराकरण करने हेतु वाट्सएप पर भेजें. एक बार में केवल एक प्रमुख समस्या ही वाट्सएप पर लिखकर भेजें. वाट्सएप हेल्पलाइन नं. 6262166222.

समस्या-समाधान
कृषक जगत 14, इंदिरा प्रेस काम्प्लेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल (म.प्र.)
फोन-0755-4248100,2554864

कृषक जगत
बागवानी सीरीज

साग-सब्जी उत्पादन उन्नत तकनीक	सब्जियों में पौध संरक्षण	मशरूम एक लाभ अनेक	मिर्च की उन्नत खेती	केला उत्पादन	गुलाब बहुरंगी संशोधित संस्करण
रु. 95	रु. 75	रु. 45	रु. 55	रु. 70	रु. 75
कोड : 016	कोड : 017	कोड : 019	कोड : 020	कोड : 025	कोड : 027

पपीता	अदरक	फलों की खेती	सजाएं फूलों से बगिया	घर की बगिया
रु. 55	रु. 55	रु. 75	रु. 65	रु. 95
कोड : 031	कोड : 032	कोड : 040	कोड : 041	कोड : 050

डाक द्वारा मंगवाने हेतु निम्नलिखित जानकारी के साथ हमारे पते पर ड्राफ्ट/मनीऑर्डर के साथ ऑर्डर कीजिए . किताब कोड नं. पर ✔ निशान लगाएं

016 ☐ 017 ☐ 019 ☐ 020 ☐ 025 ☐ 027 ☐ 031 ☐ 032 ☐ 034 ☐ 040 ☐ 041 ☐ 050 ☐

नाम ____
ग्राम ____ पोस्ट ____ तह. ____
जिला ____ फोन/मोबा. ____
कुल राशि ____ ऑर्डर की गई प्रतियों की संख्या ____
संलग्न ड्राफ्ट नं. ____ मनी आर्डर रसीद क्र. ____ वी.पी. भेजें ☐

संस्थाओं द्वारा अधिक संख्या में प्रतियां खरीदने पर आकर्षक छूट. अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें.

कृपया ड्राफ्ट या मनीआर्डर कृषक जगत भोपाल के नाम
14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल - 462011
फोन : 0755-4248100, 2554864, मो.: 9826255861, Email-info@krishakjagat.org
इंदौर : 331-332, आर्बिट माल, ए.बी. रोड, विजय नगर चौराहे के पास, इंदौर (म.प्र.) मो. : 9826021837

स्वास्थ्य/ शिक्षण

आम आदमी स्ट्रोक को कैसे जानें?

स्ट्रोक और ब्रेन अटैक दो अलग-अलग प्रकार के होते हैं-इस्केमिक प्रकार का ब्रेन अटैक मस्तिष्क में रक्त आपूर्ति कम हो जाने के कारण होता है जिसकी वजह रक्त आपूर्ति करने वाली आर्टरी में ब्लॉकेज मानी जाती है। यह ब्लॉकेज शरीर में कहीं भी रक्त थक्का बन जाने से हो सकता है, जो धीरे-धीरे मस्तिष्क की आर्टरी तक पहुंच जाता है और व्यवधान पैदा करता है। एथेरोस्क्लेरोटिक गंदगी के कारण रक्तनलिका (आर्टरी) संकीर्ण होने के बाद यह व्यवधान या ब्लॉकेज पैदा होता है। हेमोरेजिक प्रकार का ब्रेन अटैक मस्तिष्क में रक्तस्राव के कारण होता है, जिसकी वजह हाइपरटेंशन, धमनियों की कमजोर दीवारों में दरार (रक्तनलिकाओं में सूजन वाला क्षेत्र), वैस्क्यूलर विकृति (विकृत रक्तनलिकाएं फुलने से बने क्षेत्र) और कई अन्य कारक हैं।

ब्रेन अटैक के लक्षण

ब्रेन अटैक के शुरुआती लक्षण और संकेत हैंचेहरे, बांह, पैर (खासकर शरीर के एक तरफ) में अचानक संवेदन शून्यता या कमजोरी, अचानक भ्रम की स्थिति, बोलने या किसी बात को समझने में दिक्कत, एक या दो आंखों से देखने में अचानक दिक्कत, चलने में अचानक तकलीफ, चक्कर आना, संतुलन या समन्वय का अभाव, आम तौर पर सब्राकनोइड हेमरेज में बिना वजह अचानक भयंकर सिरदर्द होने लगता है। इसके साथ ही उल्टी, दौरा या मानसिक चेतना का अभाव जैसी शिकायतें भी होती हैं। इन मामलों में नॉन-कॉन्ट्रास्ट सीटी तत्काल करा लें।

कितनी खतरनाक है यह बीमारी?

स्ट्रोक के कारण मस्तिष्क में नुकसान से पूरा शरीर प्रभावित हो सकता है-जिसके परिणामस्वरूप आंशिक से लेकर गंभीर विकलांगता तक आ सकती है। इनमें पक्षाघात, सोचने, बोलने की दिक्कतें और भावनात्मक समस्याएं शामिल हैं। भारत जैसे निम्न आय और मध्य आय वर्ग वाले देश में असमय मौत और विकलांगता लिए स्ट्रोक एक अहम कारण बनता जा रहा है क्योंकि इन जगहों की जनसंख्या स्थितियां बदली हैं और कई प्रमुख परिवर्तनकारी रिस्क फैक्टर्स बढ़े हैं। स्ट्रोक झेल चुके ज्यादातर लोग

विकलांगता की स्थिति में जी रहे हैं और लंबे समय से उनके स्वास्थ्य लाभ तथा देखभाल का जिम्मा उनका परिवार ही उठा रहे हैं जिस वजह से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति और बदतर हो रही है।

किस वजह से होती है यह बीमारी?

मस्तिष्क तक रक्तकी सप्लाई करने वाली आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाने के कारण मस्तिष्क तक सप्लाई घट जाने के कारण ब्रेन अटैक होता है। यह ब्लॉकेज शरीर में कहीं भी रक्तथक्का बन जाने से हो सकता है, जो धीरे-धीरे मस्तिष्क की आर्टरी तक पहुंच जाता है और व्यवधान पैदा करता है। यह एथेरोस्क्लेरोटिक गंदगी के कारण संकीर्ण होती आर्टरी में रक्त थक्का जमने से हो सकता है। इसके कई रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं- जिन रिस्क फैक्टर्स में आप सुधार नहीं ला सकते हैं। उम्र-उम्र बढने के साथ ही खतरा भी बढ़ता जाता है। लिंग- पुरुषों में स्ट्रोक का खतरा अधिक रहता है। नस्ल- पश्चिमी देशों की तुलना में भारतीय सहित एशियाइयों में स्ट्रोक का खतरा अधिक रहता है पारिवारिक पृष्ठभूमि भी स्ट्रोक और हृदय रोग में अहम भूमिका निभाती है, जिन रिस्क फैक्टर्स में सुधार किया जा सकता है, हाइपरटेंशन- 140/90 एमएमएचजी से अधिक रक्तचाप अटैक का खतरा पर्याप्त रूप से बढ़ा देता है। दरअसल हाइपरटेंशन को 'खामोश हत्यारा' भी कहा जाता है।

हृदय रोग

एट्रियल फाइब्रिलेशन जैसे रोग और अन्य डिसऑर्डर इस खतरे को बढ़ा देता है। कैरोटिड आर्टरी रोग- कैरोटिड (ग्रीवा) धमनियां मस्तिष्क तक रक्तसप्लाई करती हैं और इसके संकीर्ण होने से ब्रेन अटैक की संभावना बढ़ जाती है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल- यह भी खतरा बढ़ाता है। धूम्रपान- धूम्रपान करने वालों को अधिक खतरा रहता है, जो धूम्रपान त्यागने से ही कम हो सकता है। डायबिटीज- यह भी खतरा बढ़ाता है, इसे खानपान, गोलियों या इंसुलिन से नियंत्रित किया जा सकता है। मोटापा- बहुत अधिक वजन, खासकर कमर के पास का वजन बढ़ने से खतरा बढ़ाता है। गैरकानूनी दवाएं- नसों में ली जाने वाले मादक पदार्थ, कोकीन के दुरुपयोग से यह खतरा बढ़ता है। उच्च रक्तचाप स्ट्रोक का एकमात्र सबसे बड़ा खतरा है जो ब्लॉकेज (इस्केमिक स्ट्रोक) के कारण 50 प्रतिशत स्ट्रोक का कारण बनता है। यह मस्तिष्क (जिसे हेमरेजिक स्ट्रोक कहा जाता है) में रक्तस्राव का खतरा भी बढ़ाता है। अच्छी खबर यह है कि कई क्लिनिकल ट्रायल्स से स्पष्ट हुआ है कि हाइपरटेंशन का दवाओं से इलाज कराने पर स्ट्रोक से बचा जा सकता है और एक अन्य शोध से भी स्पष्ट हुआ है कि एंटीहाइपरटेंसिव दवा उपचार से 32 प्रतिशत तक स्ट्रोक का खतरा कम हुआ है।

नाश्ता न करना स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है

नाश्ता न करना सेहत पर भारी पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सुबह का नाश्ता प्रोटीन के पोषण वाला होना चाहिए। इसमें अनाज, दूध, मेवे, पोहा, इडली, दलिया, उपमा या अंडे शामिल कर सकते हैं। वहीं नाश्ता न करने से इंसान को ये बीमारियां हो सकती हैं।

मधुमेह : नाश्ता नहीं करने वालों में टाइप 2 मधुमेह का खतरा रहता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लीनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित शोध के मुताबिक सुबह नाश्ता नहीं करने से शरीर में इंसुलिन के प्रति गंभीर प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है।

वजन बढ़ना : कई शोध में यह बात सामने आई है कि लोग सुबह का नाश्ता करते हैं उन्हें वजन संबंधी समस्या नहीं होती है। अगर आप सुबह का नाश्ता छोड़ते हैं, तो दोपहर के खाने में पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करेंगे।

हृदय संबंधी रोग

पोषण में भरपूर नाश्ता करने वालों से हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा कोसों दूर रहता है, जबकि सुबह नाश्ता नहीं करने से उच्च रक्तचाप और मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है।

संज्ञान संबंधी समस्या

अमेरिका डाइटिक एसोसिएशन की ओर से प्रकाशित कराए गए शोध के मुताबिक सुबह नाश्ता करने से संज्ञान संबंधी समस्याएं नहीं होती हैं।

मांसपेशियां कमजोर

मांसपेशियों के निर्माण के लिए सही पोषण देने का उपयुक्त समय सुबह ही है। सुबह खाली पेट रहने से मांसपेशियों का निर्माण प्रभावित होगा।

शक्तियों से भरपूर बादाम

- बादाम तेल से कब्ज दूर होती है और यह शरीर को ताकतवर बनाता है।
- पूरे परिवार के लिए आदर्श टॉनिक बादाम तेल का सेवन फूड एडिटिव के तौर पर किया जा सकता है।
- यह पेट की तकलीफों को दूर करने के साथ आंत की कैंसर में भी उपचारी है।
- बादाम तेल के नियमित सेवन से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। यानी यह दिल की सेहत के लिए भी अच्छा है।
- बादाम मस्तिष्क और स्नायु प्रणालियों के लिए पोषक तत्व है।
- यह बौद्धिक ऊर्जा बढ़ाने वाला, दीर्घायु बनाने वाला है।
- मीठे बादाम तेल के सेवन से माँसपेशियों में दर्द जैसी तकलीफ से तत्काल आराम मिलता है।
- बादाम तेल का प्रयोग रंगत में निखार लाता है और बेजान त्वचा को रौनक प्रदान करता है। त्वचा की खोई नमी लौटाने में भी बादाम तेल सर्वोत्तम माना गया है।
- शुद्ध बादाम तेल तनाव को दूर करता है। दृष्टि पैनी करता है और स्नायु के दर्द में भी राहत दिलाता है।
- विटामिन डी से भरपूर बादाम तेल बच्चों की हड्डियों के विकास में भी योगदान करता है।
- बादाम तेल से रूसी दूर होती है और बालों की साज-सँभाल में भी यह कारगर है। इसमें मौजूद विटामिन तथा खनिज पदार्थ बालों को चमकदार और सेहतमंद बनाते हैं।
- बादाम तेल का इस्तेमाल बाहर से किया जाए या फिर इसका सेवन किया जाए, यह हर लिहाज से उपचारी और उपयोगी साबित होता है।
- हर रोज रात को 250 मिग्रा गुनगुने दूध में 5-10 मिली बादाम तेल मिलाकर सेवन करना लाभदायक होता है।
- त्वचा को नरम, मुलायम बनाने के लिए भी आप इसे लगा सकते हैं।
- नहाने से 2-3 घंटे पहले इसे लगाना आदर्श रहता है। बादाम तेल की मालिश न सिर्फ बालों के लिए अच्छी होती है, बल्कि मस्तिष्क के विकास में भी फायदेमंद होती है। हफ्ते में एक बार बादाम तेल की मालिश गुणकारी है।

पाक्षिक पंचांग

9 से 22 मार्च 2026 तक
विक्रम संवत् 2082/83
चैत्र कृष्ण 6 तक चैत्र शुक्ल 4 तक

दि.	माह	वार		तिथि	त्यौहार
09	मार्च	सोम	चैत्र कृष्ण	6	एकनाथ छठ
10	मार्च	मंगल	----------	7	भानु सप्तमी
11	मार्च	बुध	----------	8	शीतलाष्टमी
12	मार्च	गुरु	----------	9	
13	मार्च	शुक्र	----------	10	
14	मार्च	शनि	----------	11	खरमास प्रारंभ
15	मार्च	रवि	----------	11	पापमोचनी एकादशी
16	मार्च	सोम	----------	12	प्रदोष व्रत
17	मार्च	मंगल	----------	13	शिव चतुर्दशी व्रत
18	मार्च	बुध	----------	14	
19	मार्च	गुरु	----------	30/1	चैत्र नवरात्रारंभ
20	मार्च	शुक्र	चैत्र शुक्ल	2	
21	मार्च	शनि	----------	3	गणगौर तीज व्रत
22	मार्च	रवि	----------	4	विनायकी चतुर्थी व्रत

इफको की गतिविधियां

इफको नैनो उर्वरक किसानों के लिये महत्वाकांक्षी: डॉ. बड़ोनिया

बैतूल (कृषक जगत)। इफको ने नैनो उर्वरक आधारित कृषि अधिकारी प्रशिक्षण का आयोजन उप संचालक कृषि कार्यालय के बैठक हाल में किया। इस अवसर पर डॉ. ए.के. बड़ोनिया उपसंचालक कृषि ने सम्बोधित करते हुए इफको उत्पाद किसानों के लिए महत्वाकांक्षी बताये। कार्यक्रम में डॉ. डी.के. सोलंकी राज्य विपणन प्रबंधक इफको म.प्र. एवं डॉ. एस.के. तिवारी कृषि वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल बाजार उपस्थित थे।

नैनो उर्वरकों पर विस्तारपूर्वक तकनीकी प्रशिक्षण के साथ नैनो उर्वरकों की महत्वता व भविष्य में इनकी उपयोगिता पर चर्चा की गई। डॉ. सोलंकी ने नैनो उर्वरकों के उपयोग, लाभ एवं उपयोग सावधानियों पर जानकारी दी साथ ही प्रदेश में किए जा रहे कार्यक्रमों, नवाचारों से अवगत कराया। प्रशिक्षण में सहायक संचालक कृषि श्री सुरेन्द्र पराहते, श्री रामवीर सिंह राजपूत, श्री जयपाल पटेल, श्री दीपक सरयाम, उप संचालक कृषि कार्यालय के श्री वाय. के. गुजरे, खाद्य सुरक्षा मिशन के श्री प्रकाश खातरकर, श्री सुरेन्द्र बिजांडे, एसएडीओ श्री एम. के. तायवाडे (जिला मुख्यालय), श्रीमती अलका कुडापे (बैतूल), श्री गोपाल साहू (आमला), श्री एस एल टेकाम (भैंसदेही), इफको के जिला अधिकारी श्री गौरव पाटीदार सहित अन्य कृषि अधिकारी मौजूद थे।

इफको ने हतुनिया में मनाया प्रक्षेत्र दिवस

मन्दसौर (कृषक जगत)। जिले के ग्राम हतूनिया में इफको द्वारा प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र डॉ. राजेश गुप्ता,वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी श्री चेतन पाटीदार, सरपंच श्री गोपाल पाटीदार, इफको आरजीबी सदस्य श्री कुलदीप सिंह सिसोदिया मौजूद थे। कार्यक्रम में पराली प्रबंधन,वेस्ट डीकंपोजर के उपयोग,जल घुलनशील उर्वरकों और विशिष्ट उर्वरकों के महत्व एवं नैनो उर्वरकों और इफको के अन्य उत्पादों को अपनाने के लाभ बताए एवं उनके उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया।

नैनो उर्वरकों का उपयोग करने वाले किसानों ने अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम का संचालन इफको के क्षेत्रीय प्रतिनिधि श्री आदित्य पाटीदार ने किया।

इफको उत्पाद से लहलहाती फसलों का प्रदर्शन

रायसेन (कृषक जगत)। इफको नैनो उर्वरक एवं अन्य इफको उत्पादों का फसलों पर उपयोग करने से रबी सीजन की प्रमुख फसल गेहूं लहला गई। ज़िले के ग्राम गुदावल के किसान श्री द्वारिका प्रसाद विश्वकर्मा ने खेत पर गेहूं एचआई 1650 में सागरिका, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी उर्वरक का उपयोग किया। इफको अधिकारियों की देखरेख में फसल बुवाई की गई थी। गत दिवस फसलों का अवलोकन इफको के डॉ. योगेंद्र कुमार विपणन निदेशक द्वारा किया गया। किसान द्वारा विपणन निदेशक को पारंपरिक उर्वरक की मात्रा कम कर नैनो उर्वरकों के उपयोग से प्राप्त लाभ के बारे में बताया। प्रक्षेत्र दिवस पर डॉ. दिनेश कुमार सोलंकी राज्य विपणन प्रबंधक, इफको मध्यप्रदेश, श्री रजनीश पांडेय उप महाप्रबंधक विपणन, डॉ. ओमशरण तिवारी वरिष्ठ विपणन प्रबंधक इफको भी उपस्थित थे।

कृषक जगत की सदस्यता हेतु संपर्क करें

शैलेन्द्र फरक्या, बलराम एंड ब्रदर्स, पिपलिया मंडी, जिला- मन्दसौर, मो. : 9893189345
सतीशचन्द्र शर्मा, मे. शर्मा एग्रो एजेन्सी, पनवाड़ी, जिला-शाजापुर, मो. : 9893296531
विशाल पाटीदार, मे. गायत्री कृषि एवं बीज भंडार, शुजालपुर मंडी, मो. : 8120700900

उन्हेल में किसानों की समस्याओं पर प्रदर्शन

उज्जैन (कृषक जगत/शिवनारायण नंदेडा)। खेती किसानी में हो रही समस्याओं के लिए क्षेत्र के लगभग 60 गांव के किसानों ने मोटर साइकिल,बैलगाड़ी एवं ट्रैक्टर ट्रॉली की रैली निकाली। लगभग 500 वाहनों के साथ चल रहे किसानों ने कृषि समस्याओं के समाधान हेतु नारे लगाए जिनमें-

'जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा'।

'किसान तू रहेगा मोन तो तेरी सुनेगा कौन... '।

'अभी तो यह अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है.... '।

'जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है... '।

'जय जवान जय किसान' आदि नारे लगाए गए। कस्बे के पशु हाट बाजार से शुरू हुई रैली विभिन्न क्षेत्रों से गुजरी एवं कृषि मंडी में समाप्त हुई। रैली का नेतृत्व श्री बालेश्वर आंजना किसान नेता करनावद द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्री शंकर पटेल, श्री करण कुमारिया, श्री राकेश पाटीदार कलाल खेड़ी, श्री जीवन मालवीय सरपंच पासलोद सहित सैंकड़ों किसान मौजूद थे।

78 वर्ष
कृषक जगत
राष्ट्रीय कृषि अखबार
भोपाल-जयपुर-रायपुर

वर्ष में कई आकर्षक एवं संग्रहणीय विशेषांक

- खरीफ विशेषांक
- पौध संरक्षण विशेषांक
- रबी विशेषांक
- बीज विशेषांक
- बागवानी विशेषांक

25 लाख पाठक

कृषक जगत की सदस्यता राशि
⇨ वार्षिक रु. 600/- ⇨ दो वर्ष रु. 1000/-
⇨ तीन वर्ष रु. 1500/-

डाक से नियमित रूप से **'कृषक जगत'** – प्रति सप्ताह ◻ भोपाल ◻ जयपुर ◻ रायपुर संस्करण निम्न पते पर एक वर्ष/दो वर्ष / तीन वर्ष भेजें. (अपनी आवश्यकता के अनुरूप निशान लगायें).

नाम .....
.....
ग्राम .....पो. .....
डाक वितरण हेतु अपने क्षेत्रीय पोस्टमैन का मो. नं. अवश्य दें : .....
वि.ख. ..... तह. .....
जिला ..... पिन ◻◻◻◻◻◻ राज्य .....
शिक्षा ..... भूमि ..... उम्र .....
ट्रैक्टर/मॉडल ..... फोन/मो. .....
ई-मेल .....
मेरा सदस्यता शुल्क रुपये ..... नगद/डिमांड ड्राफ्ट/UPI/Bank/
मनीऑर्डर/क्र. ..... 'कृषक जगत' भोपाल के नाम संलग्न है।

कृषक जगत में सदस्यता लेने के माध्यम
कृषक जगत ऑनलाइन पेमेंट लिंक
http://www.krishakjagat.org/krishak-jagat-subscription/index.php
Online Payment- SBI-A/C No. 53007193070, IFSC : SBIN 0005793, Google Pay/Phone Pe/PAYTM/UPI : Mobile 9826255861
कृषक जगत हेल्पलाइन नम्बर 6262166222

पेमेंट के बाद : 1. पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजें इस फोन नम्बर पर 9826255861
2. पूरा नाम, पता पिन कोड के साथ भेजें।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें
प्रसार प्रबंधक कृषक जगत

भोपाल : 14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल-462011 फोन: 0755-4248100, मो. : 9926653355, 9826255861, E-mail-info@krishakjagat.org
जयपुर : एच-64, मीरा मार्ग, बनी पार्क, जयपुर (राज.), मो. : 9829254092, 7387422952
रायपुर : एलआईजी-5, सेक्टर-2, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.),मो.: 9826255862
इंदौर : 331-332, आर्बिट माल, ए.बी. रोड, विजय नगर चौराहे के पास इंदौर, मो. : 9826021837, 9826024864
नई दिल्ली : 403,आईएनएस बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली, मो. : 7387422952

सदस्यता शुल्क भुगतान के लिए QR कोड स्कैन करें

ऑनलाईन सदस्यता के लिए लॉग इन करें
www.krishakjagat.org

संतुलित खेती : एक व्यावहारिक विकल्प

पिछले कुछ दशकों में खेती का तरीका तेजी से बदला है। उत्पादन बढ़ाने की कोशिश में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग लगातार बढ़ता गया। शुरुआती दौर में इनसे अच्छी पैदावार मिली, लेकिन समय के साथ कई नई समस्याएँ सामने आने लगीं। मिट्टी की गुणवत्ता कमजोर होने लगी, कीटों में दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई और फसलों में नई-नई बीमारियाँ और वायरस दिखाई देने लगे। परिणाम यह हुआ कि हर नई फसल के साथ रसायनों की मात्रा बढ़ती गई और किसान एक ऐसे चक्र में फँस गया जहाँ समाधान ही धीरे-धीरे समस्या बनता चला गया।

आय पर असर

दिलचस्प बात यह है कि अधिकांश किसान इन समस्याओं को समझते हैं, लेकिन फिर भी केमिकल का उपयोग कम नहीं कर पाते। इसकी सबसे बड़ी वजह उत्पादन घटने का डर है। पूरी तरह जैविक खेती अपनाना हर किसान के लिए तुरंत संभव नहीं होता, क्योंकि कई बार इससे पैदावार कम हो जाती है और आय पर असर पड़ता है। इसी वजह से खेती में ऐसे रास्ते की तलाश शुरू हुई जो मिट्टी की सेहत भी बचाए और उत्पादन भी स्थिर रखे। किसानों की इसी तलाश का परिणाम 'संतुलित खेती' एक सामाजिक अभियान की तरह चल पड़ी है।

छोटे-छोटे बदलाव

मध्यप्रदेश के सीहोर जिले के मंजरकुई गाँव के किसान मुकेश साहू भी इस बदलाव की एक मिसाल हैं। लगभग दस एकड़ जमीन पर खेती करने वाले मुकेश पहले रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का भरपूर उपयोग करते थे। उन्हें मालूम था कि ज्यादा केमिकल डालने से ही अच्छी पैदावार मिलती है। लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने महसूस किया कि खेत की मिट्टी पहले जितनी स्वस्थ और उपजाऊ नहीं रही। साथ ही फसल को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए हर साल पहले से ज्यादा दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। जब मुकेश ने इस समस्या का हल ढूँढना शुरू किया, तो उन्हें 'संतुलित खेती' के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने एकदम से खेती का तरीका बदलने के बजाय धीरे-धीरे छोटे-छोटे बदलाव करना शुरू किया। उन्होंने रासायनिक उर्वरकों की मात्रा कम की, खेत में गैर-रासायनिक पोषक तत्वों का उपयोग बढ़ाया और कीट नियंत्रण के लिए कुछ वैकल्पिक, गैर-रासायनिक उत्पादों का इस्तेमाल शुरू किया। दिलचस्प बात यह रही कि पहले जहाँ उनकी पैदावार लगभग 20 क्विंटल प्रति एकड़ थी, इन बदलावों के बाद भी उत्पादन लगभग उसी स्तर पर बना रहा।

गैर-रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग

इसी तरह **नसरुल्लागंज क्षेत्र के तिलाड़िया गाँव के किसान शंकर सिंह चौहान** का अनुभव भी 'संतुलित खेती' से कृषि में हो रहे बदलाव को दिखाता है। वे कई वर्षों से अपनी जमीन पर सोयाबीन और गेहूँ जैसी फसलों की खेती करते आ रहे हैं। पहले वे हर सीजन में कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का बढ़ती मात्रा में उपयोग करते थे। किसानों से जुड़े एक क्षेत्रीय कार्यक्रम में उन्हें जानकारी मिली कि रसायनों के ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी में मौजूद जैविक कार्बन की मात्रा लगातार कम हो रही है, जिससे मिट्टी की उर्वरता पर बुरा असर पड़ रहा है। इसके बाद शंकर सिंह चौहान ने शुरुआत में केवल 20-25 प्रतिशत तक केमिकल कम करने का प्रयोग किया और 'संतुलित खेती' से जुड़कर कुछ गैर-रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग शुरू किया। पहले ही सीजन में उन्होंने देखा कि उत्पादन लगभग पहले जैसा ही बना रहा और केमिकल का उपयोग लगभग 20 प्रतिशत तक कम हो गया। इससे उनका भरोसा बढ़ा और अब वे हर साल धीरे-धीरे रसायनों की मात्रा घटाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

जैविक कार्बन स्तर घटा

आंकड़ों के अनुसार 1950 के दशक में भारतीय मिट्टी में जैविक कार्बन का स्तर लगभग 1 प्रतिशत था, जो आज कई क्षेत्रों में घटकर केवल 0.3-0.4 प्रतिशत रह गया है। यह स्तर स्वस्थ और उत्पादक मिट्टी के लिए आवश्यक मानक से काफी कम माना जाता है। यदि यह और नीचे चला गया तो भूमि की उर्वरता गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है।

इसी पृष्ठभूमि में संतुलित खेती को एक व्यवहारिक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इसकी खास बात यह है कि किसान को अचानक सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं होती। वह अपनी परिस्थितियों और सहूलियत के अनुसार धीरे-धीरे रसायनों की मात्रा कम कर सकता है और उत्पादन लगभग पहले जैसा ही बना रहता है।

यदि इसे व्यापक स्तर पर अपनाया गया, तो यह मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने और घटती जैविक गुणवत्ता को सुधारने में मदद कर सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आने वाली पीढ़ियों को भी उपजाऊ जमीन मिल सकेगी। इस तरह संतुलित खेती न केवल आज के किसानों के लिए फायदेमंद है, बल्कि मिट्टी को स्वस्थ रखकर भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी खेती की मजबूत नींव तैयार करती है।

खरगोन में कृषि आदान विक्रेता संघ का जिला स्तरीय सम्मेलन संपन्न

खरगोन (दिलीप दसौंधी, कृषक जगत)। कृषि आदान विक्रेता संघ द्वारा खरगोन में जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष श्री मानसिंह राजपूत, प्रदेश सचिव श्री संजय रघुवंशी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण दुबे तथा प्रदेश सदस्यता प्रभारी श्री विनोद जैन विशेष रूप से उपस्थित रहे। इनके अलावा जिलाध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह चावला सहित अन्य पदाधिकारी एवं जिले भर से बड़ी संख्या में कृषि आदान विक्रेता शामिल हुए। प्रदेश एवं जिला स्तर के पदाधिकारियों ने व्यापारियों को वर्तमान व्यापारिक परिस्थितियों, शासन के नए नियमों तथा संगठन की भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में लगभग 350 से अधिक व्यापारी उपस्थित थे।

श्री राजपूत ने कहा कि वर्तमान समय में शासन द्वारा व्यापार से संबंधित कई सख्त कानून लागू किए जा रहे हैं, जिनसे भविष्य में व्यापारियों के सामने कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। यदि समय रहते व्यापारी संगठित नहीं हुए, तो छोटे व्यापारियों के सामने व्यापार बंद होने जैसी स्थिति भी आ सकती है। उन्होंने संगठन की एकजुटता को व्यापारियों की सबसे बड़ी ताकत बताया। वहीं श्री रघुवंशी ने व्यापारियों से संगठन के निर्देशों का पालन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन लेनदेन से सावधानी बरतते हुए जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय संगठन को मजबूत बनाना आवश्यक है। उन्होंने खाद, बीज और कीटनाशक के नमूने फेल होने की स्थिति में बचाव के उपायों तथा संबंधित कानूनों की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया संगठन और प्रदेश संगठन द्वारा पिछले सात वर्षों में किए गए प्रयास आगे भी जारी रहेंगे।

श्री जैन ने संगठन को मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक व्यापारियों को सदस्यता अभियान से जोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यदि किसी बीज या दवाई का एक लॉट फेल होता है, तो केवल उसी लॉट को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, न कि पूरे लाइसेंस को, क्योंकि इससे व्यापारी और उनका परिवार प्रभावित होता है।

श्री दुबे ने व्यापारियों से सदस्यता अभियान में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान करते हुए कहा कि यदि भविष्य में सीड एक्ट और पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल के विरोध में न्यायालय में याचिका दायर की जाती है ,तो केवल पंजीकृत सदस्यों को ही उसका लाभ मिल सकेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से इन कानूनों में संशोधन करने की मांग भी की। जिलाध्यक्ष श्री चावला ने बताया कि खरगोन जिले में लगभग 1400 कृषि आदान से जुड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान संचालित हैं। संगठन का लक्ष्य है कि सभी प्रतिष्ठानों को सक्रिय सदस्य बनाया जाए। इसके लिए जल्द ही जिलेभर में चरणबद्ध सदस्यता अभियान चलाया जाएगा तथा तहसील स्तर पर बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस अवसर पर कई व्यापारियों ने राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता ग्रहण की। प्रारंभ में श्री चावला, श्री राजेंद्र पाटीदार ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार श्री राजू पाटीदार द्वारा किया गया।

भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सरी
ISO 9001 : 2015 सर्टिफाइड
किसान हाईटेक ग्रीनहाऊस नर्सरी
द्वारा पपीता, मिर्च, टमाटर, बैंगन, तरबूज, करेला, पत्तागोभी, फूलगोभी आदि सब्जी के पौधे टेबल स्टेण्ड के ऊपर रखकर तैयार किए जाते हैं
सम्पर्क : 9407361901, 9407361902, 9407361903
सहयोगी प्रतिष्ठान : बागवानी बाजार नर्सरी
जहां पर फलदार, सजावटी व फारेस्टी पौधों की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। संपर्क : मो. : 9407853117, 9407853118, 9407853119, नर्सरी स्थल : ग्राम-सिरलाय, तह.- बड़वाह 451115, जिला-खरगोन (म.प्र.)
मार्च 26

TerraGlebe Farmers Producer Company Limited
NIMADFRESH
यूरोप में मिर्च निर्यात (एक्सपोर्ट) करने वाला मध्यप्रदेश का पहला किसान उत्पादक संगठन बना 'टेरागलेब'
अब उसी की तर्ज पर नाबार्ड से गठित FPO निमाड़फ्रेश FPO रसायन मुक्त मसाले का बना मैन्युफैक्चर ODOP - मिर्च-खरगोन
निमाड़फ्रेश FPO (JV) हरिओम भुरे 8964087240
टेरागलेब FPO बालकृष्ण पाटीदार 9575524408
जुलाई 26

पटवारी एग्रो एजेन्सी
:: वितरक ::
◆ कलश सीड्स लि. ◆ बायोस्टेट इंडिया लि. ◆ बॉयर कॉप साइंस ◆ धानुका एग्रीटेक लि. ◆ एफ.एम.सी. इंडिया प्रा.लि. ◆ घरड़ा केमिकल्स लि. ◆ अतुल एग्रीटेक लि. ◆ रामा फॉस्फेट्स लि. ◆ जी.एन.एफ.सी. ◆ इंसेक्टीसाइड्स इंडिया लि. ◆ बीएएसएफ ◆ डयूपॉन्ट इंडिया लि. ◆ क्रिस्टल क्राप साइंस ◆ डाउएग्रो साइंसेस ◆ एग्री सर्च इंडिया ◆ मंशा इंडिया लि. ◆ स्वाल कार्पोरेशन लि. ◆ मेघमनी आर्गेनिक्स ◆ अदामा इंडिया लि.
17, विशाल टॉवर, इंदिरा काम्पलेक्स, नवलखा चौराहा, इन्दौर (म.प्र.)
फोन : 2403694, 2400412, मो. : 9425077083

छोटा विज्ञापन बड़ा लाभ
व्यक्तिगत क्लासीफाइड
विज्ञापन के लिए निर्धारित कैटेगरीज-
- बेचना/खरीदना- ट्रैक्टर, ट्राली, थ्रेशर, खेत, मकान, मोटरसाइकल, पशु, मोटर, जनरेटर आदि ■ बीज ■ औषधीय फसल
विज्ञापन दर - मात्र रु. 600/- प्रति संस्करण लगातार 4 सप्ताह तक ■ अधिकतम 25 शब्द
- अतिरिक्त शब्द- 2 रु. प्रति शब्द, अधिकतम 40 शब्दों तक
डिस्प्ले क्लासीफाइड
विज्ञापन दर : रु. 800/- प्रति अंक, प्रति संस्करण जीएसटी 5%अतिरिक्त
साइज : फिक्स साइज- 8 × 5 = 40 वर्ग से.मी.
कैटेगरीज- बीज, कीटनाशक, जैविक खाद, ट्रेक्ल्स, तीर्थ यात्राएं, आवश्यकता, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, कृषि सेवा केन्द्र, शिक्षण संस्थाएं, प्रशिक्षण, बारदाने, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, होस्टल, वित्तीय संस्थाएं, चिकित्सक, एग्री क्लीनिक आदि।
कृषक जगत
की सदस्यता एवं विज्ञापन के लिए हेल्पलाइन नं.
62 62 166 222
www.krishakjagat.org @krishakjagatindia
@krishakjagat @krishak_jagat

एस्कॉर्ट्स कुबोटा ने 'साउथ स्पेशल' धान ट्रैक्टर सीरीज लॉन्च की

फरीदाबाद (कृषक जगत)। एस्कॉर्ट्स कुबोटा ने दक्षिण भारत के धान क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए 'साउथ स्पेशल' पावरट्रैक शौर्य ट्रैक्टर सीरीज लॉन्च की है। 39 एचपी से 52 एचपी श्रेणी में उपलब्ध इस नई सीरीज में पाँच वैरिएंट शामिल हैं। यह पहली बार है जब Powertrac ब्रांड ने विशेष रूप से धान और जलभराव वाली भूमि के लिए समर्पित ट्रैक्टर रेंज पेश की है।

यह सीरीज तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे प्रमुख धान उत्पादक राज्यों की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित की गई है। कंपनी का कहना है कि इससे दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण धान बाजार में उसकी मौजूदगी और मजबूत होगी।

एस्कॉर्ट्स कुबोटा भारत में तीन ट्रैक्टर ब्रांड-कुबोटा, फार्मट्रैक और पावरट्रैक के साथ काम करती है, जो क्रमशः प्रीमियम, एंट्री-प्रीमियम और वैल्यू सेगमेंट को सेवा देते हैं। पावरट्रैक कंपनी का वैल्यू और मास सेगमेंट ब्रांड है, जो विभिन्न कृषि कार्यों के लिए किफायती और उपयोगी विकल्प प्रदान करता है। शौर्य सीरीज के माध्यम से कंपनी ने फसल-विशेष और क्षेत्र-विशेष समाधान पर अपना फोकस और स्पष्ट किया है।

पावरट्रैक शौर्य सीरीज को खासतौर पर धान की खेती और जलभराव वाली परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण हिस्सों पर कैसेट-टाइप सीलिंग दी गई है, जिससे खेत में काम करते समय पानी और कीचड़ अंदर न जा सके। 3.1 मीटर का शार्प टर्निंग रेडियस छोटे और मध्यम आकार के खेतों में आसान मोड़ लेने में मदद करता है, जो दक्षिण भारत के धान क्षेत्रों की एक सामान्य विशेषता है।

लॉन्च के अवसर पर **सीएमडी श्री निखिल नंदा** ने कहा, 'दक्षिण भारत एस्कॉर्ट्स कुबोटा की अगली विकास यात्रा का महत्वपूर्ण केंद्र है। शौर्य का लॉन्च धान बाजार में हमारी पकड़ को और मजबूत करेगा और क्षेत्रीय विस्तार में मदद करेगा।'

डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अकीरा कातो ने कहा, 'शौर्य को दक्षिण भारत के धान और जलभराव वाले खेतों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है, ताकि कठिन परिस्थितियों में भी भरोसेमंद प्रदर्शन मिल सके।' होल-टाइम डायरेक्टर एवं सीएफओ भारत मदान ने कहा, 'यह पेशकश दक्षिण भारत के धान सेगमेंट में हमारी भागीदारी को मजबूत करेगी।'

ट्रैक्टर बिजनेस डिवीजन के चीफ ऑफिसर श्री नीरज मेहरा ने कहा, 'पावरट्रैक शौर्य को खासतौर पर जलभराव वाली खेती के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी बेहतर मोड़ क्षमता, सीलिंग सुरक्षा और बहुउपयोगी पीटीओ कॉन्फिगरेशन दक्षिण भारत के धान उत्पादक किसानों की जरूरतों के अनुरूप हैं।' पावरट्रैक शौर्य सीरीज दक्षिण भारत में अधिकृत पावरट्रैक डीलरशिप्स पर उपलब्ध होगी।

मैटिक्स फर्टिलाइजर्स ने शुरू की दूसरी मोबाइल मृदा परीक्षण वैन

मुंबई (कृषक जगत)। मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि. ने किसानों को वैज्ञानिक खेती में सहयोग देने के उद्देश्य से अपनी दूसरी मोबाइल मृदा परीक्षण वैन शुरू की है। इस वैन को हाल ही में कंपनी के नोएडा स्थित प्रिंसिपल मार्केटिंग ऑफिस से रवाना किया गया। यह वैन एक चलती-फिरती प्रयोगशाला की तरह काम करती है, जो किसानों के खेतों तक पहुँचकर मिट्टी की जांच करती है। जांच के आधार पर किसानों को मिट्टी की सेहत का रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है और फसल के अनुसार उर्वरक उपयोग व वैज्ञानिक खेती की सलाह भी दी जाती है।

कंपनी की यह पहल पहले से असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा में चल रही है। दूसरी वैन शुरू होने से अब उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के किसानों तक इसकी सेवाएँ और व्यापक रूप से पहुँचेंगी। इस मोबाइल प्रयोगशाला में मिट्टी का पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी (EC), फास्फोरस, पोटाश और ऑर्गेनिक कार्बन जैसे महत्वपूर्ण परीक्षण किए जाते हैं। वैन में आधुनिक उपकरण, पावर बैकअप, इंटरनेट, लैपटॉप और प्रिंटर की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे किसानों को मौके पर ही रिपोर्ट की प्रति मिल जाती है।

कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री मनोज मिश्रा ने कहा कि समय पर मिट्टी की जांच से संतुलित उर्वरक उपयोग और बेहतर फसल उत्पादन संभव होता है। यह पहल किसानों को सही निर्णय लेने में मदद करेगी और मिट्टी की दीर्घकालिक उर्वरता बनाए रखने में सहायक होगी। कंपनी के अनुसार, मोबाइल मृदा परीक्षण वैन के माध्यम से किसानों को मुफ्त मिट्टी जांच और वैज्ञानिक सलाह दी जाएगी, जिससे वे कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें।

सोनालिका ने फरवरी में 12 हजार से अधिक ट्रैक्टर बिक्री दर्ज की, कंपनी के 30 वर्ष पूरे

नई दिल्ली (कृषक जगत)। सोनालिका ट्रैक्टर्स ने वित्त वर्ष 2025-26 के फरवरी महीने में

कुल 12,890 ट्रैक्टरों की बिक्री दर्ज की है। कंपनी के अनुसार यह फरवरी महीने में अब तक की उसकी सबसे अधिक बिक्री है। इसी वर्ष कंपनी कृषि मशीनीकरण के क्षेत्र में अपने 30 वर्ष भी पूरे कर रही है।

कंपनी के अनुसार भारत में कृषि मशीनीकरण के विस्तार के साथ ट्रैक्टरों की मांग कई क्षेत्रों में बढ़ रही है। प्रिसिजन फार्मिंग और उन्नत कृषि तकनीकों के उपयोग में वृद्धि के कारण खेती में मशीनों का उपयोग बढ़ रहा है।

भारत के कृषि क्षेत्र में सरकारी नीतिगत समर्थन, मशीनीकरण को बढ़ावा देने वाली पहल, किसानों के लिए ऋण उपलब्धता और ग्रामीण अवसंरचना पर बढ़ते खर्च जैसे कारकों का प्रभाव देखा जा रहा है, जिनका उद्देश्य कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में सुधार करना है। इसके साथ ही कृषि उपकरण कंपनियां विभिन्न फसल प्रणालियों और खेती की जरूरतों के अनुसार मशीनें विकसित कर रही हैं।

सोनालिका ट्रैक्टर्स ने हाल ही में सोनालिका गोल्ड सीरीज़ के ट्रैक्टर भी पेश किए हैं। कंपनी के अनुसार ये ट्रैक्टर विभिन्न फसलों और खेती की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विकसित किए गए हैं।

कंपनी का कहना है कि खेती में श्रम उपलब्धता, खेत की कार्यक्षमता की आवश्यकता और फसल तीव्रता जैसे कारक कृषि मशीनीकरण को प्रभावित कर रहे हैं और इन परिस्थितियों में ट्रैक्टरों की भूमिका बढ़ रही

इस उपलब्धि पर टिप्पणी करते हुए **श्री रमन मित्तल, संयुक्त प्रबंध निदेशक, इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लि.** ने कहा कि देश में कृषि उत्पादन में किसानों की भूमिका महत्वपूर्ण है और ट्रैक्टर तकनीक खेती के कार्यों को समर्थन देने के लिए विकसित की जा रही है। उन्होंने कहा कि कंपनी के 30वें वर्ष में फरवरी महीने में 12,890 ट्रैक्टरों की बिक्री इस बात को दर्शाती है कि खेती में मशीनीकरण की भूमिका बढ़ रही है और कंपनी किसानों के साथ जुड़ाव बनाए रखते हुए कृषि क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार कार्य कर रही है।

ड्रिप सिंचाई से सालाना 325 मिलियन लीटर पानी बचाने के लिए

ऑर्बिया नेटाफिम और अमेज़न की साझेदारी

नई दिल्ली (कृषक जगत)। ऑर्बिया एडवांस कॉरपोरेशन के प्रिसिजन एग्रीकल्चर व्यवसाय नेटाफिम ने अमेज़न इंडिया के साथ दो जल संरक्षण पहलों की घोषणा की है, जिनके तहत बेंगलुरु और हैदराबाद के कृषि क्षेत्रों में ड्रिप सिंचाई प्रणाली लागू कर प्रतिवर्ष लगभग 325 मिलियन लीटर पानी की बचत का लक्ष्य रखा गया है।

बेंगलुरु में लौकी और टमाटर की खेती करने वाले लगभग 70 किसानों के 80 हेक्टेयर खेतों में ड्रिप सिंचाई होगी । वहीं हैदराबाद क्षेत्र में मक्का और सब्ज़ी की खेती करने वाले लगभग 40 किसानों के 40 हेक्टेयर खेतों में ड्रिप सिंचाई अपनाई जाएगी। इससे बेंगलुरु क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 175 मिलियन लीटर और हैदराबाद क्षेत्र में लगभग 150 मिलियन लीटर पानी की बचत होने का अनुमान है।

अमेज़न इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेशंस के वाइस प्रेसिडेंट श्री अभिनव सिंह ने कहा, 'इससे किसानों को अपनी सिंचाई प्रणाली की दक्षता बढ़ाने में मदद मिलेगी और जल-संकट वाले क्षेत्रों में जल सुरक्षा को भी समर्थन मिलेगा।' इस परियोजना के तहत जिन खेतों में बाढ़ सिंचाई से ड्रिप सिंचाई की ओर बदलाव होगा, वहां पानी की खपत में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है, जबकि फसल उत्पादकता और पैदावार स्थिर बनी रह सकती है।

ऑर्बिया नेटाफिम में इनोवेशन एंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस के निदेशक श्री मैक्स मोल्दाव्स्की ने कहा, 'प्रिसिजन सिंचाई किसानों और समुदायों के लिए ठोस परिणाम दे सकती है। ड्रिप सिंचाई अपनाने से पानी के उपयोग की दक्षता बढ़ती है, किसानों की आजीविका मजबूत होती है।'

महिंद्रा ने घरेलू बाजार में 35% की मजबूत वृद्धि दर्ज की

मुंबई (कृषक जगत)। महिंद्रा समूह के अंतर्गत आने वाले महिंद्रा एंड महिंद्रा लि. के कृषि उपकरण व्यवसाय (एफईबी) ने फरवरी 2026 के लिए अपने ट्रैक्टर बिक्री के आंकड़े घोषित किए। फरवरी 2026 में घरेलू बिक्री 32,153 यूनिट रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 35% की वृद्धि दर्शाती है। फरवरी 2026 के दौरान ट्रैक्टरों की कुल बिक्री (घरेलू+निर्यात) 34,133 यूनिट रही। इस माह के दौरान निर्यात 1,980 यूनिट रहा, जिसमें 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

महिंद्रा एंड महिंद्रा लि. के कृषि उपकरण व्यवसाय के 20% की वृद्धि है।'

अध्यक्ष श्री विजय नाकरा ने कहा, 'फरवरी 2026 में घरेलू बाजार में 32,153 ट्रैक्टर बेचे हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 35% की मजबूत वृद्धि दर्शाता है। रबी की बुवाई के क्षेत्र में मजबूत वृद्धि, जलाशयों में पानी का अच्छा स्तर और खरीफ की अनुकूल फसल ग्रामीण बाजारों में नकदी प्रवाह को मजबूत कर रही है। ये सकारात्मक रुझान, साथ ही इस महीने नवरात्रि, ट्रैक्टर की मांग को बढ़ाने में सहायक होंगे। निर्यात बाजार में, हमने 1,980 ट्रैक्टर बेचे हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में

जायद में मूंग पर ही भरोसा

उड़द को लेकर किसानों में संकोच

इंदौर (विशेष प्रतिनिधि, कृषक जगत)।

मध्य प्रदेश सरकार ने इस वर्ष ग्रीष्मकालीन जायद फसलों में मूंग के स्थान पर उड़द को बढ़ावा देने की पहल की है, लेकिन जमीनी स्तर पर किसान फिलहाल इस बदलाव को अपनाने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं। गेहूं कटाई के बाद जायद फसल की तैयारियों में जुटने वाले किसान अब भी मूंग को ही अधिक सुरक्षित और लाभकारी विकल्प मान रहे हैं। कृषक जगत द्वारा मूंग उत्पादक प्रमुख जिलों हरदा, नर्मदापुरम, देवास और सीहोर के किसानों से की गई बातचीत में यह स्पष्ट हुआ कि जायद में उड़द की खेती को लेकर किसानों में उत्साह कम है। किसानों का कहना है कि मूंग कम अवधि में तैयार हो जाती है, जबकि उड़द को पकने में अधिक समय लगता है। इससे खरीफ फसल की तैयारी प्रभावित होने की आशंका रहती है।

सरकारी प्रोत्साहन के बावजूद खेतों में नहीं दिख रहा उत्साह

सरकार ने हाल ही में उड़द उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त रू. 600 प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य रू.7,800 प्रति क्विंटल तय किया है। राज्य प्रोत्साहन जोड़ने पर किसानों को रू. 8,400 प्रति क्विंटल तक मिल सकते हैं। वहीं मूंग का समर्थन मूल्य 8768 रू. प्रति क्विंटल है, इसके बावजूद जायद में खेतों का रुझान अभी भी मूंग की ओर झुका हुआ दिखाई देता है। प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर अभी तक स्पष्ट घोषणा नहीं हुई है। इससे किसानों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि ग्रीष्मकालीन बोवनी में मूंग लें या उड़द।

प्रदेश में मूंग का रकबा लगभग 15 लाख हेक्टेयर है, जबकि उड़द का रकबा करीब 95 हजार हेक्टेयर मात्र ही है। ऐसे में स्थापित बीज और सिंचाई व्यवस्था के कारण बड़े पैमाने पर मूंग से उड़द की ओर तत्काल बदलाव आसान नहीं माना जा रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि मूंग खरीदी पर जल्द स्पष्ट नीति नहीं आती है तो बोवनी से पहले किसानों के लिए निर्णय लेना कठिन हो सकता है। फिलहाल किसानों की नजर सरकार की अगली घोषणा पर टिकी हुई है।

'मूंग 60 दिन में तैयार, उड़द में 70-90 दिन'

हरदा जिले के ग्राम जिनवान्या के किसान श्री करण पटेल ने बताया कि क्षेत्र में फिलहाल चने की कटाई चल रही है और करीब 8-10 दिन बाद गेहूं कटाई शुरू हो जाएगी। इसके बाद वे लगभग 30-35 एकड़ में जायद मूंग की बुवाई करेंगे। उनका कहना है कि मूंग की फसल लगभग 60 दिन में तैयार हो जाती है, जबकि उड़द को पकने में करीब 70-90 दिन लगते हैं। इससे खरीफ की तैयारी के लिए समय कम पड़ जाता है। उनके अनुसार हरदा जिले में जायद में उड़द की खेती की संभावना 10 प्रतिशत से भी कम है। हरदा के ही किसान श्री केदार सिरोही ने सरकार द्वारा जायद में मूंग की जगह उड़द को प्राथमिकता देने की पहल पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्षेत्र के किसान वर्षों से मूंग की खेती करते आ रहे हैं और बाजार में इसकी मांग भी स्थिर रहती है। उनका कहना है कि बिना पर्याप्त तकनीकी अध्ययन के अचानक फसल परिवर्तन का निर्णय व्यवहारिक नहीं है।

बिजली कटौती और समय की कमी भी बड़ी बाधा

घाटली (इटारसी) के किसान श्री शरद वर्मा का कहना है कि उनके क्षेत्र में जायद में मुख्यतः मूंग और मक्का की खेती होती है और वे इस वर्ष भी यही फसलें लगाएंगे। उन्होंने बताया कि हर वर्ष गेहूं कटाई के दौरान आगजनी की आशंका के कारण बिजली विभाग लगभग 15 दिन तक बिजली आपूर्ति बंद कर देता है, जिससे कृषि कार्य प्रभावित होते हैं। ऐसी स्थिति में लंबी अवधि वाली उड़द की खेती करने पर खरीफ फसल की तैयारी में मुश्किल हो सकती है।

इटारसी के किसान श्री संजय चिमानिया ने बताया कि वे इस वर्ष लगभग 35 एकड़ में जायद मूंग लगाएंगे। उनका कहना है कि उड़द में कीट एवं रोग का प्रकोप अधिक रहता है और बाजार भाव भी स्थिर नहीं होते। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि सरकार चाहती है कि किसान गर्मी में खेत खाली रखें तो इसके लिए उन्हें आर्थिक राहत या प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इससे भूमि की सेहत भी बेहतर रहेगी और रसायनों के अत्यधिक उपयोग की समस्या भी कम हो सकती है।

उड़द में उत्पादन और भाव दोनों का जोखिम

सीहोर जिले के ग्राम चिचलाय के किसान श्री सुनील पवार ने बताया कि इस वर्ष भी वे लगभग 35 एकड़ में जायद मूंग लगाएंगे। पिछले वर्ष उन्हें मूंग का 7 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन मिला था। उन्होंने बताया कि जायद में उड़द की खेती का प्रयोग पहले कर चुके हैं, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं रहे। उत्पादन और बाजार भाव दोनों अपेक्षा से कम मिले थे।

उड़द को प्रोत्साहन, मूंग पर सस्पेंस

तेजपुरा (सीहोर) के किसान श्री धर्मेंद्र पवार का कहना है कि वे इस वर्ष 20 एकड़ में मूंग लगाएंगे। हालांकि प्रयोग के तौर पर थोड़े क्षेत्र में उड़द भी बो सकते हैं।

देवास जिले के सत्रौड़ गांव के किसान श्री सत्यनारायण पटेल ने बताया कि क्षेत्र में घोड़रोज (नीलगाय) की समस्या के कारण कई किसान जायद की फसल लेने से बचते हैं। वे इस वर्ष सीमित क्षेत्र में तिल्ली की खेती करेंगे, जिसमें दवा का खर्च कम होता है और पशुओं से नुकसान का खतरा भी कम रहता है।

पदमपुरा (देवास) के किसान श्री सर्वेश केलवा ने बताया कि वे गेहूं कटाई के बाद जायद में मूंग ही लगाएंगे। पिछले वर्ष 15 एकड़ में मूंग से उन्हें 5-6 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन मिला था। उनका कहना है कि यदि उड़द की कम अवधि वाली किस्म उपलब्ध हो तो किसान इसे अपनाने पर विचार कर सकते हैं।

नीति और जमीन के बीच दूरी

कुल मिलाकर किसानों की प्रतिक्रियाओं से यह संकेत मिलता है कि जायद में उड़द को बढ़ावा देने की सरकारी पहल फिलहाल नीति और व्यवहार के बीच की दूरी से जूझ रही है। किसान पारंपरिक अनुभव, फसल अवधि, बाजार भरोसे और मौसमीय जोखिम को ध्यान में रखते हुए मूंग को ही अधिक सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं।

ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार जायद में उड़द का रकबा बढ़ाना चाहती है, तो केवल प्रोत्साहन राशि पर्याप्त नहीं होगी। इसके लिए कम अवधि वाली उन्नत किस्में, तकनीकी मार्गदर्शन, भरोसेमंद खरीद व्यवस्था और क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुसार नीति बनानी होगी। तभी खेतों में बदलाव की तस्वीर दिखाई दे सकेगी।

ADVT